वर्ष-11, अंक-11, अगस्त-2026
मूल्य : ₹20

वेलकम इंडिया

RNI No. UPHIN/2015/61611
राष्ट्रीय मासिक हिन्दी पत्रिका

भाजपा का मिशन-2027

विकास • विश्वास • सुशासन

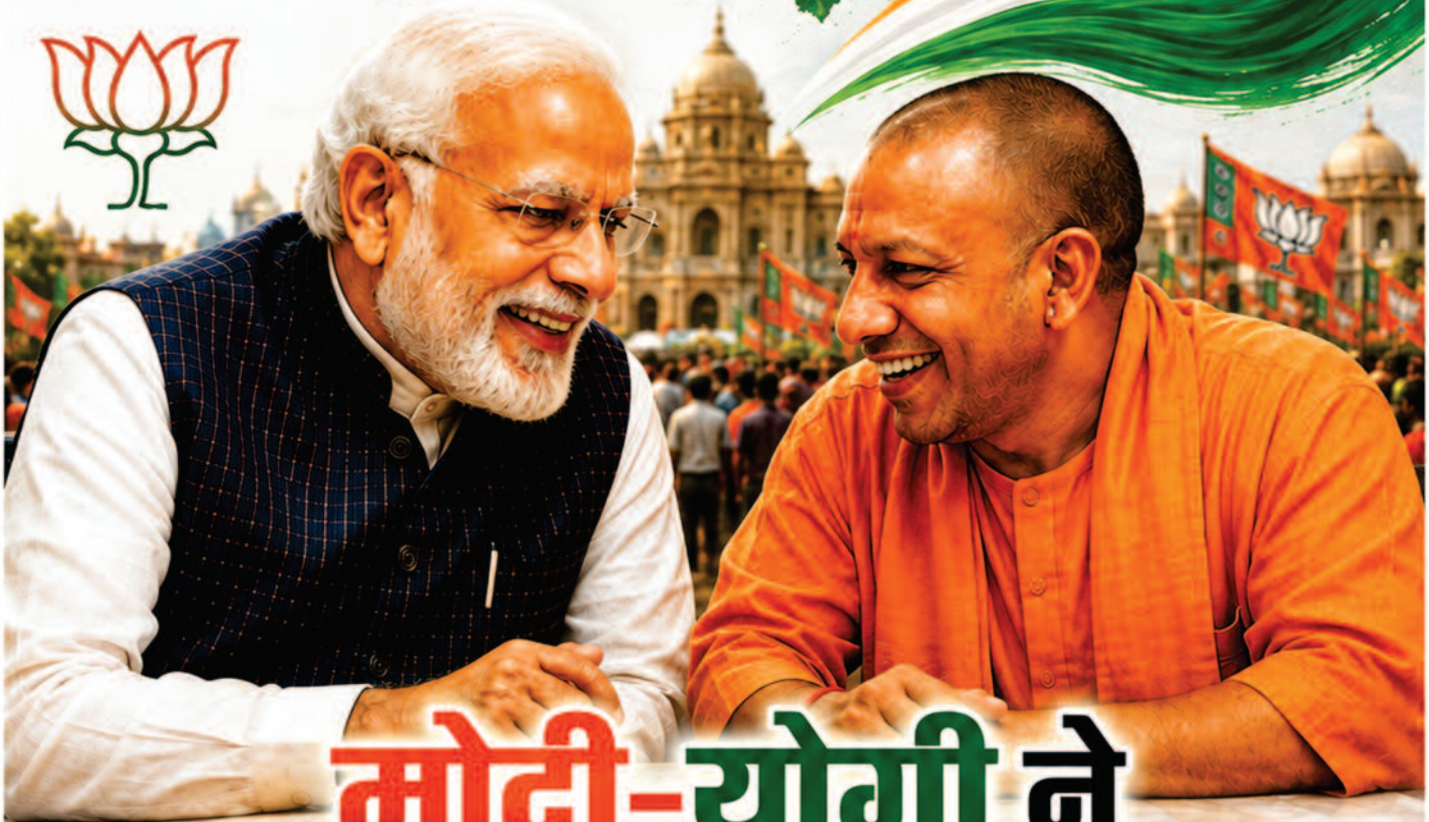

मोदी-योगी ने बनाई रणनीति

विशेष लेख
नया भारत नई दिशा

प्रदेश फोकस
यूपी की बदलती तस्वीर

गाउंड रिपोर्ट
जनता की जुबानी विकास की कहानी

युवा संवाद
युवाओं के सपने मजबूत भारत

सबका साथ • सबका विकास • सबका विश्वास • सबका प्रयास

जागरूकता ही है बचाव का रास्ता

सुरक्षित स्कूली वाहन

पहली प्राथमिकता

शैक्षणिक सत्र में सुरक्षित स्कूली वाहनों से हो विद्यार्थियों का आवागमन

प्रदेश के सभी विद्यालयों के प्रबंधकों से अपील

- स्कूल वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण
- 12 वर्ष तक के विद्यार्थियों के परिवहन में प्रयुक्त स्कूल वाहनों में एक परिचारक/परिचारिका की अनिवार्यता
- वाहन के सुरक्षा मानकों, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन यंत्र, इमरजेंसी अलार्म आदि उपकरणों की प्रतिमाह हो जांच
- स्कूल वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा एवं अन्य आनुषंगिक प्रपत्रों की वैधता की नियमित जांच तथा अनफिट वाहनों का बहिष्कार

याद रखिए, छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूल वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन तथा अभिभावकों एवं स्कूली प्रबंधन की सजगता अत्यंत आवश्यक है।

परिवहन हेल्पलाइन
149 | 1800-1800-151

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076

सुरक्षित बचपन-विकसित उत्तर प्रदेश

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP

वर्ष- 11 अंक- 11

अगस्त-2026

सम्पादक ललित कुमार शर्मा

कार्यकारी सम्पादक
अनादि शुक्ल, प्रशांत शर्मा
संजय बंसल, संजीव शर्मा

संरक्षक
स्व. वेद प्रकाश शर्मा
अभिषेक गर्ग, एनके शर्मा, प्रवीण चौधरी
अमिताभ शुक्ल, अरुण शर्मा,
प्रभाकर त्यागी, डॉ. निमित त्यागी

वरिष्ठ सलाहकार
विजय अरोडा, राहुल अग्रवाल,
सचिन तोमर, देवनाथ कुमार

सम्पादकीय सहयोगी
डॉ. बी. जमां

बिजनेस हेड
रजनीकांत शर्मा/विकास पंडित

कानूनी सलाहकार
कीर्तिकर सुकुल (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
वंदना शर्मा भंडारी (एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट)
अनिल आनंद, नीरज सत्संगी

मुद्रक, स्वामी, प्रकाशक, सम्पादक ललित कुमार द्वारा अवनीर एन्टरप्राईजेज, ए-7/105, इंडस्ट्रीयल एरिया साउथ साईड जी.टी. रोड गाजियाबाद से मुद्रित कराकर ग्राउंड फ्लोर 150, दुर्गा टॉवर, आरडीसी राजनगर गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
सम्पादक - ललित कुमार शर्मा
RNI No. UPHIN/2015/61611
ई-मेल: winews.in@gmail.com
वेबसाइट: www.winews.in
सम्पर्क सूत्र: 9891116568

नोट: पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद के लिए गाजियाबाद न्यायालय मान्य होगा।

भाजपा का मिशन 2027

मोदी-योगी ने बनाई रणनीति

दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड में डालते हुए नई नियुक्तियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने छह संगठनात्मक क्षेत्रों और विभिन्न मोर्चों के प्रभारियों की घोषणा की है। नई टीम में करीब 60 फीसदी नए चेहरों को जगह दी गई है।

कवर स्टोरी पेज-28

अंतरिक्ष में भारत की निजी शक्ति एवं वैज्ञानिक सामर्थ्य की उड़ान — पेज 03

प्रधानमंत्री मोदी का लालकिले से 'विकसित भारत' का संकल्प — पेज 06

एडीसीपी ट्रैफिक वरुण कुमार सिंह से वेलकम इंडिया की खास बातचीत... — पेज 12

योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड: उपलब्धियां विपक्ष के सवाल और जनता का फैसला — पेज 16

कभी पिता के पुराने स्कूटर पर दुकान का सामान लाते थे 'यश' आज हैं सुपरस्टार — पेज 53

वनडे क्रिकेट के 5000 मैच पूरे, सचिन तेंदुलकर का 18426 रन का रिकॉर्ड आज भी कायम — पेज 55

विज्ञापन, समाचार के लिए वेलकम इंडिया दैनिक एवं मासिक पत्रिका के जोनल सम्पादक कृष्णराज अरुण से मोबाइल नम्बर 9802414328 /9813221734 पर सम्पर्क करें।

नेपाल में बाढ़ की तबाही ने फिर चेताया, हिमालय से छेड़छाड़ कितनी भारी पड़ेगी?

तिब्बत से लगे नेपाल के रसुवा और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार को आई बाढ़ से बड़े पैमाने पर हुए जान-माल के नुकसान ने सभी को झकझोर दिया है। इस त्रासदी में कई लोगों की जान चली गई, जबकि पांच सौ से ज्यादा लापता हैं, जिनमें सौ से अधिक भारतीय भी शामिल हैं। बाढ़ से कई पुल बह गए और कम से कम एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। खबरों के मुताबिक, सबसे पहले भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आई, जिससे तिब्बत की सीमा से लगे नेपाल के रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। पानी और मलबे का बहाव इतना तेज था कि आसपास के धादिंग, नुवाकोट और चितवन जिले भी इसकी चपेट में आ गए। बाढ़ से लापता भारतीयों में से ज्यादातर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। नेपाल के बाढ़ पूवार्नुमान प्रभाग के मुताबिक, पहाड़ी से चट्टानों एवं मिट्टी के खिसकने से नदी अवरुद्ध हो गई और वहां बनी झील के टूटने से भीषण बाढ़ आई।

यह त्रासदी इस बात का संकेत है कि हिमालयी क्षेत्र पारिस्थितिकीय रूप से कितना संवेदनशील है। प्रकृति हमें जल, वायु, भूमि, वन और जीवन के लिए आवश्यक अनेक संसाधन प्रदान करती है। मगर विकास और आधुनिक जीवन की दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने के बजाय उसका अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया है। जंगलों की कटाई, पहाड़ों का अतिक्रमण, नदियों के मार्गों में हस्तक्षेप और अनियोजित निर्माण जैसे कार्यों का परिणाम बाढ़ जैसी विनाशकारी त्रासदियों के रूप में सामने आ रहा है।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन नदियों को नेपाल की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा-संभावना की जीवनरेखा माना जाता है, उन्हीं के किनारे बेतरतीब बस्तियां, सड़कें और अन्य ढांचागत संरचनाएं तैयार कर दी गई हैं। विकास आवश्यक है, लेकिन इस क्रम में पहाड़ों की प्रकृति की अनदेखी अंततः जोखिम का विस्तार बन जाती है। जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। मौसम का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है, तो कहीं बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा या बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं।

साफ है कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बाढ़ जैसी त्रासदी को जन्म देती है। बहरहाल, विदेश मंत्रालय का कहना है कि नेपाल में बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के बचाव और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए वहां की सरकार के साथ लगातार संपर्क एवं समन्वय किया जा रहा है। मगर, इस बाढ़ से नेपाल के साथ लगते बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी खतरा मंडराने लगा है। केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वहां एहतियाती तौर पर सुरक्षा के माकूल प्रबंध किए जाएं, ताकि किसी तरह के नुकसान से बचा जा सके।

ललित कुमार
सम्पादक

इस त्रासदी में कई लोगों की जान चली गई, जबकि पांच सौ से ज्यादा लापता हैं, जिनमें सौ से अधिक भारतीय भी शामिल हैं। बाढ़ से कई पुल बह गए और कम से कम एक दर्जन जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। खबरों के मुताबिक, सबसे पहले भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आई, जिससे तिब्बत की सीमा से लगे नेपाल के रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए।

अंतरिक्ष में भारत की निजी शक्ति एवं वैज्ञानिक सामर्थ्य की उड़ान

संजीव कुमार

भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल सरकारी संस्थानों और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह गई है। यह यात्रा आज नवाचार, उद्यमिता, युवा प्रतिभा, निजी पूंजी और वैश्विक महत्वाकांक्षा के ऐसे संगम में बदल रही है, जिसने भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की दिशा में एक नई गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी सहभागिता के द्वार खोलने का निर्णय इसी परिवर्तन का निर्णायक पड़ाव है। कभी जिस अंतरिक्ष क्षेत्र को लगभग पूरी तरह सरकारी नियंत्रण और संस्थागत सीमाओं के भीतर देखा जाता था, आज वहां सैकड़ों नवोदित उद्यम अपने सपनों, तकनीक और साहस के साथ नई संभावनाओं का आकाश तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय निजी अंतरिक्ष उद्यमियों से संवाद कर उन्हें प्रेरित करना केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य के भारत की दिशा का उद्घोष है। इसमें उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ भारत को विश्व की अंतरिक्ष प्रतिभा, निवेश और उद्यमिता का आकर्षण-केंद्र बनाने का सपना प्रस्तुत किया, वह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का भी संकेत है। भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों का इतिहास अपने आप में असाधारण है। सीमित संसाधनों के बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जिस वैज्ञानिक अनुशासन, आत्मनिर्भरता और संकल्प का परिचय दिया, उसने दुनिया को चकित किया है। आर्यभट्ट से प्रारंभ हुई यात्रा मंगलयान तक पहुंची, चंद्रयान ने चंद्रमा के रहस्यों को समझने की भारतीय क्षमता सिद्ध की और चंद्रयान-3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बनाकर इतिहास रचा। यह उपलब्धि केवल एक वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, यह भारतीय प्रतिभा, तकनीकी आत्मविश्वास और असंभव को संभव करने की राष्ट्रीय क्षमता का प्रमाण थी। मंगलयान ने कम लागत में अंतरग्रहीय अभियान की सफलता से दुनिया को भारत की वैज्ञानिक दक्षता का परिचय दिया। आदित्य-एल1 ने सूर्य के अध्ययन की दिशा में भारत की महत्वाकांक्षा को नई ऊंचाई दी। अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति की तैयारी से जुड़ा गगनयान अभियान भारत की अगली बड़ी छलांग का संकेत है। इस पूरी यात्रा ने यह स्पष्ट किया है कि भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान में केवल उपलब्धियों का अनुकरण करने वाला देश

नहीं, बल्कि नए मानदंड स्थापित करने की क्षमता रखने वाला राष्ट्र है।

इस उपलब्धि की अगली स्वाभाविक कड़ी निजी क्षेत्र की भागीदारी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद भारत में लगभग 440 अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी नवोदित उद्यमों का उभरना इस परिवर्तन की गहराई को दर्शाता है। इनमें कुछ उपग्रह निर्माण में लगे हैं, कुछ प्रक्षेपण यानों की तकनीक विकसित कर रहे हैं, कुछ अंतरिक्ष आधारित आंकड़ों के विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पृथ्वी अवलोकन, संचार, मौसम पूवार्नुमान और अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन जैसी अत्याधुनिक दिशाओं में काम कर रहे हैं। स्काईरूट एयरोस्पेस ने निजी क्षेत्र के रॉकेट प्रक्षेपण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है, जबकि अग्निकुल कॉसमॉस ने स्वदेशी तकनीक और आधुनिक निर्माण पद्धतियों के माध्यम से यह दिखाया है कि भारतीय निजी उद्यम अंतरिक्ष प्रक्षेपण के कठिन क्षेत्र में भी अपनी जगह बना सकते हैं। ये प्रयास उस मानसिकता को बदल रहे हैं जिसमें अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों का क्षेत्र माना जाता था। अब यह युवा उद्यमियों के लिए रोजगार, अनुसंधान, निवेश और वैश्विक व्यापार का नया क्षेत्र बन रहा है। इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अंतरिक्ष अब केवल आकाश में उपलब्धियों का विषय नहीं, बल्कि धरती पर जीवन को बेहतर बनाने का साधन भी बन रहा है। उपग्रह आधारित सेवाएं कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, फसल की निगरानी करने, जल संसाधनों की पहचान, मौसम की सटीक जानकारी देने, मछली पालन, वन संरक्षण और आपदा प्रबंधन में उपयोगी हो सकती हैं। बाढ़, चक्रवात, सूखा और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय अंतरिक्ष से प्राप्त सूचनाएं राहत और बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बना सकती हैं। गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में संचार तथा डिजिटल सेवाओं के विस्तार में भी अंतरिक्ष तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब केवल वैज्ञानिक गौरव का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास का शक्तिशाली माध्यम बन रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिक्ष संबंधी दृष्टिकोण इसी व्यापक सोच पर आधारित दिखाई देता है। उनका सपना भारत को केवल अंतरिक्ष में पहुंचने वाला देश बनाना नहीं, बल्कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अग्रणी शक्ति बनाना है। वे चाहते हैं कि दुनिया की प्रतिभाएं भारत आएं, भारतीय युवा अंतरिक्ष क्षेत्र में नए विचारों के साथ आगे बढ़ें और भारत वैश्विक अंतरिक्ष कंपनियों तथा निवेशकों के लिए विश्वसनीय केंद्र बने। यह दृष्टिकोण भारत की आर्थिक शक्ति को नई दिशा दे सकता है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में संचार, मौसम, रक्षा, कृषि, परिवहन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं के साथ गहराई से जुड़ने वाली है। ऐसे में जो देश इस क्षेत्र में तकनीकी नेतृत्व स्थापित करेगा, उसकी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति भी बढ़ेगी। निजी अंतरिक्ष उद्यमों के सामने संभावनाएं जितनी बड़ी हैं, चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं।

अंतरिक्ष तकनीक में अनुसंधान और विकास के लिए भारी पूंजी चाहिए। प्रक्षेपण की असफलता का जोखिम सामान्य उद्योगों की तुलना में कहीं अधिक होता है। अत्यंत जटिल तकनीक, कठोर सुरक्षा मानक, कुशल मानव संसाधन और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता इस क्षेत्र को कठिन बनाती है। इसलिए सरकार की भूमिका केवल नियम बनाने तक सीमित नहीं रह सकती।

उसे ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो नवाचार को प्रोत्साहित करें, निजी उद्यमों को परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराएं, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाएं तथा निवेशकों का विश्वास कायम रखें। अंतरिक्ष क्षेत्र की एकल खिड़की व्यवस्था और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रही हैं।

भारत के लिए एक और बड़ी संभावना अंतरिक्ष में लागत और दक्षता की अपनी पारंपरिक ताकत को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। भारत ने पहले ही यह सिद्ध किया है कि सीमित लागत में उच्च गुणवत्ता वाली अंतरिक्ष सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। यदि यही क्षमता निजी क्षेत्र की गति, नवाचार और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति से जुड़ती है तो भारत छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण, उपग्रह निर्माण, अंतरिक्ष आधारित आंकड़ों और वैश्विक अंतरिक्ष सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा बाजार हासिल कर सकता है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जन के साथ-साथ उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अनुभव निजी क्षेत्र के लिए अमूल्य पूंजी है। दशकों की वैज्ञानिक साधना से अर्जित ज्ञान, प्रक्षेपण तकनीक, उपग्रह निर्माण की क्षमता और मिशन प्रबंधन का अनुभव अब देश के नवोदित उद्यमों के लिए मार्गदर्शक शक्ति बन सकता है। सरकारी संस्थान और निजी उद्यम यदि प्रतिस्पर्धा के साथ सहयोग की संस्कृति विकसित करें तो भारत की अंतरिक्ष शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। सरकार का काम रास्ता खोलना है, वैज्ञानिक संस्थानों का काम ज्ञान और अनुभव उपलब्ध कराना है और निजी क्षेत्र का काम गति, नवाचार और बाजार की शक्ति को आगे बढ़ाना है। इन तीनों का समन्वय भारत को नई ऊंचाई दे सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान कि भारत ऐसा वातावरण बनाए जहां दुनिया भर के युवा अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए यहां आने की सोचें, वास्तव में प्रतिभा की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की नई आकांक्षा को व्यक्त करता है। यह केवल रॉकेटों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है, यह भारत को अंतरिक्ष आधारित ज्ञान, तकनीक और अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाने की कल्पना है। आने वाले समय में अंतरिक्ष में भारत की सफलता का मूल्यांकन केवल कितने उपग्रह भेजे गए या कितने रॉकेट छोड़े गए, इससे नहीं होगा। असली कसौटी यह होगी कि अंतरिक्ष तकनीक ने भारतीय

किसान, विद्यार्थी, उद्यमी, सैनिक, वैज्ञानिक और सामान्य नागरिक के जीवन को कितना बेहतर बनाया।

भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब उस मुकाम पर है जहां आकाश सीमा नहीं, बल्कि अवसर है। चंद्रयान-3 की चंद्र विजय से लेकर सूर्य की ओर आदित्य-एल1 की यात्रा, मंगलयान की ऐतिहासिक सफलता से लेकर मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी और सरकारी संस्थानों से निकलकर निजी स्टार्टअप के प्रक्षेपण तक भारत ने लंबी दूरी तय की है। अब अगला अध्याय और अधिक महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आवश्यकता है कि वैज्ञानिक जिज्ञासा को उद्यमिता से, सरकारी नीति को निजी ऊर्जा से और भारतीय प्रतिभा को वैश्विक अवसरों से जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिक्ष विजन इसी समन्वय को दिशा देता है। भारत ने धरती से चंद्रमा तक अपनी क्षमता सिद्ध कर दी है, अब चुनौती है कि वह अंतरिक्ष में अपनी वैज्ञानिक शक्ति के साथ-साथ आर्थिक, तकनीकी और मानवीय नेतृत्व की भी ऐसी छाप छोड़े, जिसे दुनिया लंबे समय तक याद रखे। यही नई अंतरिक्ष उड़ान आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत की व्यापक आकांक्षा से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी का लालकिले से 'विकसित भारत' का संकल्प

इस व्यापक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए देश के चार प्रमुख वर्गों को विकास का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिन्हें युवा, महिला, किसान और गरीब के रूप में रेखांकित किया गया है। इन चारों स्तंभों के समग्र सशक्तिकरण के बिना किसी भी विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

अनादि शुक्ल

ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर केवल पत्थरों की एक संरचना नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के उतार-चढ़ाव, उसकी आकांक्षाओं, उसकी नियति और उसके सामूहिक संकल्पों की मूक गवाह रही है। हर वर्ष 15 अगस्त को इस प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो वह केवल एक औपचारिक भाषण नहीं होता, बल्कि वह आने वाले समय के लिए देश का नीतिगत और वैचारिक रोडमैप होता है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी ऐतिहासिक प्राचीर से वर्ष 2047 तक भारत को एक 'विकसित राष्ट्र' बनाने का जो अटूट संकल्प दोहराया है, वह देश की समकालीन राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक युगांतकारी मोड़ है। 'विकसित भारत' का यह विजन महज एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक चेतना को जगाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण के एक महायज्ञ में आहुति देने के लिए प्रेरित करने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय दर्शन है। जब हम इस विराट संकल्प की बात करते हैं, तो हमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ और प्रासंगिकता को गहराई से समझना होगा। भारत ने लगभग दो सदियों तक औपनिवेशिक दासता और आर्थिक शोषण का दंश झेला है। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तब हमारी अर्थव्यवस्था जर्जर थी, साक्षरता दर दयनीय थी और अकाल तथा गरीबी जैसी बुनियादी चुनौतियां हमारे सामने थीं। शुरूआती दशकों में भारत का मुख्य ध्यान आत्मनिर्भरता और बुनियादी अस्तित्व की रक्षा पर था। हमने खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति की, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य तंत्र को मजबूत किया और धीरे-धीरे एक ठोस औद्योगिक आधार

तैयार किया। आज, स्वतंत्रता के इस दौर में, भारत उस स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है और अब हम केवल एक अस्तित्व बनाए रखने वाले देश नहीं हैं, बल्कि हम वैश्विक पटल पर एक नई दिशा तय करने वाले राष्ट्र बन चुके हैं। यह संकल्प इस बात का प्रतीक है कि अब भारत अपनी विकासशील छवि के खोल को तोड़कर वैश्विक शक्तियों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2047 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष होगा, और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर दुनिया के सामने अपनी सफलता का क्या प्रमाण प्रस्तुत करता है, यही उसका वास्तविक ऐतिहासिक मूल्यांकन होता है।

इस व्यापक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए देश के चार प्रमुख वर्गों को विकास का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिन्हें युवा, महिला, किसान और गरीब के रूप में रेखांकित किया गया है। इन चारों स्तंभों के समग्र सशक्तिकरण के बिना किसी भी विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है और हमारी जनसांख्यिकीय लाभांश हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विकसित भारत का सपना तभी सच हो सकता है जब इस युवा ऊर्जा को सही दिशा, उत्कृष्ट शिक्षा और वैश्विक स्तर का कौशल मिले। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। इसके साथ ही, विकसित भारत का दूसरा अनिवार्य पहलू महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके नेतृत्व में होने वाला विकास है। जब तक देश की आधी आबादी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह सक्रिय नहीं होगी, तब तक विकास की रफ्तार अधूरी रहेगी। सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती महिलाओं की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि वे अब नीति निर्धारण के केंद्र में आ रही हैं। इसी तरह, भारत की आत्मा आज भी गांवों में बसती है और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार, आधुनिक खेती को बढ़ावा और वैश्विक कृषि आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना आवश्यक है। किसान जब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक कृषि-उद्यमी बनेगा, तभी ग्रामीण भारत समृद्ध होगा। अंत में, अंत्योदय की भावना के अनुरूप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक कि बहुआयामी गरीबी का पूरी तरह उन्मूलन न हो जाए और हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन स्तर न मिल जाए।

आर्थिक मोर्चे पर, भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और शीर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की ओर अग्रसर है। लेकिन विकसित देश बनने के लिए हमें केवल सकल घरेलू उत्पाद के आकार को ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में भी गुणात्मक सुधार करना होगा। इसके लिए विनिर्माण और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल देना आवश्यक है। 'मेक इन इंडिया' अभियान के तहत भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। रक्षा क्षेत्र में, जहां कभी हम पूरी तरह आयातों पर निर्भर थे, आज हम स्वदेशी अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं और उनका निर्यात भी बढ़ा रहे हैं। भारतीय कॉर्पोरेट जगत को अब वैश्विक कंपनियों की तर्ज पर अपनी क्षमता का विस्तार करना होगा ताकि भारतीय ब्रांड दुनिया भर के बाजारों में अग्रणी भूमिका निभा सकें। इसके साथ ही, देश के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया जा रहा है। आधुनिक रेलवे, एक्सप्रेसवे का विस्तृत नेटवर्क, जलमार्गों का विकास और हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक मजबूत और आधुनिक बुनियादी ढांचा ही विकसित भारत की ठोस नींव बनेगा, जो देश के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।

तकनीक और नवाचार के इस युग में जो देश अग्रणी रहेगा, वही दुनिया के भविष्य को दिशा देगा। भारत ने डिजिटल क्षेत्र में जो क्रांति की है, उसने दुनिया के विकसित देशों को भी अचंभित किया है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था आज वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बन चुकी है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं है, बल्कि वह विश्व को सस्ती, सुरक्षित और समावेशी तकनीक देने वाला प्रदाता भी है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ता निवेश इस विजन को और स्पष्ट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत का बढ़ता कदम यह दर्शाता है कि हम भविष्य की तकनीकों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और संप्रभु होना विकसित भारत की एक अनिवार्य शर्त है, जो हमें वैश्विक मंच पर एक अद्वितीय

पहचान दिलाएगी।

संकल्प जितना विराट होता है, उसकी राह की चुनौतियां भी उतनी ही कठिन होती हैं। विकसित भारत के मार्ग में कई आंतरिक और बाह्य चुनौतियां हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता को पाटना एक बड़ी चुनौती है। विकास का लाभ समाज के हर वर्ग और देश के हर कोने तक समान रूप से पहुंचना चाहिए। इसके अलावा, भारत को पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच एक कुशल संतुलन बनाना होगा। जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना युद्धस्तर पर आवश्यक है। प्रशासनिक स्तर पर, हमारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-अनुकूल बनना होगा, क्योंकि लालफीताशाही और भ्रष्टाचार विकास की गति को धीमा करते हैं। वैश्विक मोर्चे पर, वर्तमान समय की भू-राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक व्यवधान भी हमारे सामने चुनौतियां खड़ी करते हैं, जिनसे निपटने के लिए भारत को अपनी कूटनीतिक कुशलता और आंतरिक आर्थिक सुदृढ़ता को निरंतर मजबूत बनाए रखना होगा।

इस पूरे महायज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश के नागरिकों की है। कोई भी देश केवल सरकार की नीतियों, बजट या घोषणाओं से विकसित नहीं बनता। सरकार मार्ग प्रशस्त कर सकती है, बुनियादी ढांचा दे सकती है, लेकिन उस पर चलकर देश को आगे ले जाने का काम नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव होता है। विकसित भारत का संकल्प तब तक अधूरा है जब तक देश का हर नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह सजग नहीं होता। चाहे वह करों का ईमानदारी से भुगतान करना हो, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हो, पर्यावरण को बचाना हो, या फिर अपने-अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ योगदान देना हो—ये सभी नागरिक प्रयास मिलकर एक विशाल राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करते हैं। जब देश के नागरिक 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लेंगे, तो भारत की प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा।

निष्कर्षतः विकसित भारत का संकल्प केवल आर्थिक आंकड़ों या ऊंची इमारतों तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, तकनीकी रूप से अग्रणी हो, सामाजिक रूप से समरस और न्यायपूर्ण हो, और सांस्कृतिक रूप से अपनी समृद्ध जड़ों से जुड़ा हुआ हो। यह एक ऐसे भारत का सपना है जहां हर नागरिक को समान अवसर, उत्कृष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा मिले। लालकिले की प्राचीर से गूंजा यह संकल्प देश के लिए एक महान आह्वान है। आने वाले दो दशक भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहे हैं। यदि हम सब मिलकर पूरी निष्ठा और राष्ट्रीय गौरव की भावना के साथ इस संकल्प के प्रति समर्पित हो जाएं, तो निश्चित रूप से वर्ष 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहा होगा, तब वह विश्व पटल पर एक परम वैभवशाली, समर्थ और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा।

NEET-UG 2026 से भर्ती परीक्षाओं तक

पेपर लीक ने युवाओं के भविष्य पर खड़ा किया बड़ा सवाल

आज भारत में युवाओं का वह भरोसा पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका है। दस गुना दस फुट के सीलन भरे कमरे में रातें जागकर काटने वाला युवा जब अखबार में प्रश्नपत्र लीक की खबर पढ़ता है, तो केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार अंदर से टूट जाता है।

कपिल शर्मा

हमारे देश में सरकारी नौकरी या प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना किसी भयानक और जानलेवा अग्निपरीक्षा से कम नहीं रह गया है। व्यवस्था की यह क्रूरता केवल किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती, झारखंड के लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और राष्ट्रीय स्तर की यूजीसी-नेट जैसी परीक्षाओं के लगातार लीक होते पर्चों ने युवाओं के भविष्य को मजाक बना दिया है।

मगर टूटते सपनों की इस आग में सबसे बड़ा विस्फोट हाल ही में नीट-यूजी 2026 के महाघोटाले के रूप में सामने आया। मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की इस सबसे बड़ी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने की घटना ने देश के लाखों विद्यार्थियों को एक ऐसा गहरा मानसिक आघात दिया है, जिसकी टीस आने वाले कई सालों तक महसूस की जाएगी।

देश को हिला देने वाले इस घोटाले की शुरूआत तीन मई 2026 को हुई, जब परीक्षा के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र सब तरफ देखे जाने लगे। सीबीआई जांच में यह शर्मनाक सच सामने आया कि सेंधमारी बाहर से नहीं, बल्कि

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के अंदर से ही हुई थी। सुरक्षा की जांच-पड़ताल न होने का फायदा उठाकर गोपनीय कमरों में तैनात विषय विशेषज्ञों ने सवालों को रफ कागज पर लिखकर बाहर भेज दिया। आखिरकार पुख्ता सबूतों और भारी जनदबाव के आगे झुकते हुए एनटीए को 12 मई 2026 को परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा का जानलेवा तनाव इसके आंकड़ों से स्पष्ट है। हर साल 22-23 लाख विद्यार्थियों के बीच असली जंग केवल 63,000 सरकारी सीटों के लिए होती है, क्योंकि निजी मेडिकल कॉलेज आम विद्यार्थियों की पहुंच से दूर हैं। जब एक सीट पर छत्तीस से अधिक दावेदार हों, तो प्रश्नपत्र लीक जैसी धांधली योग्य विद्यार्थियों की सालों की तपस्या को एक झटके में तबाह कर देती है।

तंत्र की इस भूलभुलैया में आज युवा इस कदर पिस रहा है कि आवेदन करने से लेकर परीक्षा देने, प्रश्नपत्र लीक होने पर सड़कों पर लाठियां खाने और यहां तक कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी नौकरी छिन जाने तक का सफर एक अंतहीन यातना बन चुका है। इस पूरी समस्या के मूल में असीमित उम्मीदवार और सीमित अवसरों का वह मकड़जाल है, जो देश की हर प्रमुख परीक्षा को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में लगभग 900-1000 पदों के लिए हर साल 10 से 13 लाख युवा आवेदन करते हैं, जहां सफलता की दर 0.1 फीसद से भी कम है। आइआइटी-जेईई में 17-18 हजार सीटों के लिए लगभग 1.8 लाख मेधावी कतार में होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोगों का हाल तो और भी बुरा है, जहां 200 से 500 पदों के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है और यूजीसी नेट में बैठने वाले 7.5 लाख विद्यार्थियों में से जेआरएफ केवल पांच हजार को नसीब होता है। मांग और आपूर्ति के इसी भयावह अंतर और अत्यधिक दबाव का सीधा फायदा परीक्षा माफिया उठाता है।

दांव पर भविष्य

इस नीतिगत पंगुता का सबसे ताजा और दर्दनाक शिकार झारखंड बना है। जेपीएससी और जेएसएससी-सीजीएल में धांधली के खिलाफ विद्यार्थियों के 26 दिनों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने आनन-फानन में 2014 से अब तक की 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दीं। इस अदूरदर्शी फैसले ने एक मानवीय संकट खड़ा कर दिया, जिसके चलते ईमानदारी से परीक्षा पास कर पुरानी नौकरियां छोड़कर सचिवालय में सेवाएं दे रहे युवा रातों-रात बेरोजगार हो गए। हालांकि झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी।

आंकड़े चीख-चीख कर गवाही देते हैं कि यह कोई नई या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि पिछले करीब एक दशक (2014-2026) की राष्ट्रीय महामारी है। इस दौरान देश के 19 राज्यों में 152 से अधिक परीक्षाओं, नीट-यूजी (22.7 लाख विद्यार्थी) और यूजीसी-नेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं के साथ-साथ उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार लोक सेवा आयोग और ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा, हरियाणा में एचएसएससी समूह डी तथा सीटेट जैसी कई राज्य-स्तरीय परीक्षाएं प्रश्नपत्र लीक और प्रशासनिक गड़बड़ियों के कारण रद्द हुईं, जिससे करोड़ों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया।

तंत्र की भूलभुलैया

साल 2024 से 2026 के बीच राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं ने साबित कर दिया कि एनटीए जैसी सबसे बड़ी संस्थाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। इतनी बड़ी सत्ता और मशीनरी होने के बावजूद सरकारों की इस लाचारी के तीन सबसे बड़े कारण हैं। पहला, परीक्षाओं को आउटसोर्स करके टीसीएस जैसी निजी आईटी कंपनियों या स्कूलों को ठेका दे देना, जहां चंद पैसों के लालच में कर्मचारी आसानी से सौदेबाजी कर लेते हैं। दूसरा, पेपर लीक अब कोई छिटपुट घटना नहीं, बल्कि डार्क वेब, ब्लूटूथ और

हैकिंग सॉफ्टवेयर जैसी उच्च तकनीकों से लैस हजारों करोड़ का संगठित अखिल भारतीय अपराध बन चुका है। और तीसरा, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर ट्रेजरी और परीक्षा केंद्रों तक बैठे तंत्र के 'विभीषण', जिनकी अंदरूनी सरकारी मिलीभगत के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता।

यह केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एक गहरी मानवीय त्रासदी है। जब उम्र सीमा पार होती है और सपने टूटते हैं, तो अवसाद युवाओं को आत्महत्या के अंधेरे कुएं में धकेल देता है। जंतर-मंतर पर हजारों विद्यार्थियों का प्रदर्शन, उन पर बरसती लाठियां और टूटते सपने यह बताते हैं कि यह एक 'असाध्य और जटिल बीमारी' है, जिसे अब किसी एक राजनीतिक पार्टी या राज्य के चश्मे से नहीं देखा जा सकता।

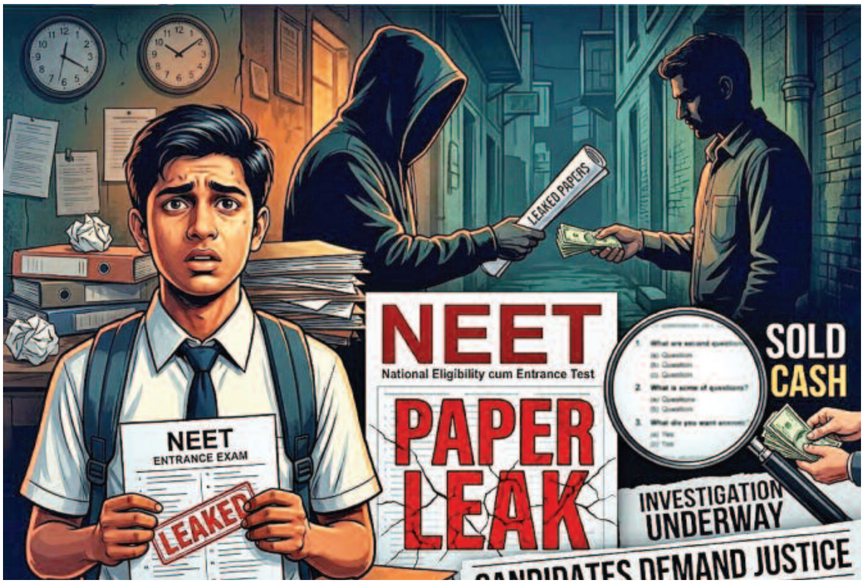

सख्ती के बावजूद

विद्यार्थियों के राष्ट्रव्यापी आक्रोश के दबाव में 'लोक परीक्षा संशोधन विधेयक, 2026' पारित किया गया, जो 2024 के मूल कानून को और अधिक सख्त बनाता है। इसके तहत व्यक्तिगत दोषियों के लिए पांच से दस साल की जेल और 50 लाख तक के जुमार्ने का प्रावधान है। वहीं प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह और इसमें सहयोग देने वालों पर एक से दस करोड़ रुपये तक का भारी जुमार्ना, काली सूची में शामिल किया जाना और त्वरित अदालतों के जरिए साठ दिन के भीतर तुरंत न्याय सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है।

सख्त कानून और साठ दिन की निश्चित अवधि उम्मीद की किरण हैं, लेकिन सजा बढ़ाने के बावजूद तब तक अपराध नहीं रुकेंगे, जब तक तंत्र के भीतर बैठे भ्रष्टाचारियों पर सीधा प्रहार न हो। सरकारों को यह समझना होगा कि दबाव में 'परीक्षाएं रद्द करना' नाकामी छिपाने का तरीका भर है। परीक्षाओं को आउटसोर्सिंग के चंगुल से निकालकर सौ फीसद सुरक्षित और एआई-आधारित सरकारी ढांचे पर लाना होगा।

आज देश का युवा एक ऐसा पारदर्शी तंत्र चाहता है, जहां उसकी योग्यता का फैसला दलालों की 'रेट-लिस्ट' से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत से हो। अगर अब भी तंत्र नहीं जागा, तो हम केवल डिग्रियां नहीं, बल्कि एक पूरी होनहार पीढ़ी का भविष्य राख में मिला रहे होंगे।

जाम से जंग, सड़क सुरक्षा पर जोर

गाजियाबाद को सुगम और सुरक्षित ट्रैफिक देने की चुनौती के बीच एडीसीपी ट्रैफिक वरुण कुमार सिंह से वेलकम इंडिया की खास बातचीत

ललित कुमार

गाजियाबाद की सड़कों पर दौड़ती हजारों गाड़ियां, हर दिन बढ़ता ट्रैफिक दबाव, पीक आवर्स में लगने वाला जाम, अव्यवस्थित पार्किंग, ई-रिक्शा और ऑटो का संचालन, सड़क किनारे अतिक्रमण और सबसे बड़ी चुनौती, सड़क हादसों में होने वाली जनहानि। दिल्ली-एनसीआर का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था महज स्थानीय समस्या नहीं, बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा विषय है।

ऐसे चुनौतीपूर्ण शहर में यातायात व्यवस्था की कमान संभालना आसान काम नहीं है। इसी जिम्मेदारी के साथ एडीसीपी ट्रैफिक वरुण कुमार सिंह गाजियाबाद कमिश्नरेट की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में आमद दर्ज कराने के उपरांत पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड द्वारा पीपीएस अधिकारी वरुण कुमार सिंह को ADCP-ट्रैफिक की महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीपीएस अधिकारी वरुण कुमार सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में अपनी सख्त अनुशासनप्रियता, त्वरित कार्यशैली, रणनीतिक सूझबूझ और लगनशीलता के लिए जाने जाते हैं। प्रशासनिक दक्षता और धरातलीय कार्यप्रणाली के धनी श्री सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही केवल कार्यालयी बैठकों तक सीमित रहने के बजाय स्वयं सड़कों पर उतरकर गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था का भौतिक स्तर पर जायजा लिया।

चार्ज लेने के उपरांत उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य गाजियाबाद कमिश्नरेट की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, सरल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है। इसके साथ ही, व्यस्त मार्गों, चौराहों और बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन क्लीन' को और अधिक आक्रामक गति प्रदान करना उनकी दैनिक कार्ययोजना का प्रमुख हिस्सा है। उनकी कार्यशैली में एक बात साफ दिखाई देती है, ट्रैफिक केवल चालान काटने का विषय नहीं है। इसमें सड़क की डिजाइन, पार्किंग, अतिक्रमण, सार्वजनिक परिवहन, वाहन चालकों की आदतें, तकनीक और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, सभी की भूमिका है।

गाजियाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था को तकनीक

से जोड़ने की दिशा में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अधिकारी के मुताबिक कमिश्नरेट में ITMS पूरी तरह संचालित है और विभिन्न स्थानों पर करीब 850 कैमरों के माध्यम से यातायात नियमों की निगरानी की जा रही है। हालिया मौकों पर भी वरुण कुमार सिंह ट्रैफिक डायवर्जन और बड़े आयोजनों के दौरान फील्ड मैनेजमेंट में सक्रिय दिखाई दिए हैं।

चार्ज संभालने के बाद उनकी प्राथमिकता स्पष्ट रही- सड़कों को जाम से राहत देना, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर कार्रवाई करना, सड़क हादसों को कम करना और लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना।

NCR का प्रमुख हिस्सा होने के नाते गाजियाबाद न केवल दिल्ली, नोएडा, मेरठ और बुलंदशहर को जोड़ता है, बल्कि यहाँ प्रतिदिन लाखों वाहनों का सघन आवागमन होता है। बढ़ती आबादी, व्यावसायिक गतिविधियों, अनधिकृत पार्किंग और निर्माण कार्यों के बीच शहर को सुचारू ट्रैफिक देना एक जटिल प्रशासनिक चुनौती है। इन परिस्थितियों के बीच **एडीसीपी वरुण कुमार सिंह** किस विजन, तकनीक और रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं, आइए जानते हैं उनसे हुई इस विशेष बातचीत के प्रमुख अंश

सवाल- गाजियाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था में इस समय आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है?

जवाब-गाजियाबाद कमिश्नरेट में ITMS पूरी तरह संचालित है। विभिन्न लोकेशन पर करीब 850 कैमरे लगाए गए हैं और इनके माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। हमारी प्राथमिकता यह है कि तकनीक का इस्तेमाल केवल चालान तक सीमित न रहे, बल्कि इससे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद मिले। हमारा प्रयास है कि शहर में लोगों को सुरक्षित और सुगम यातायात उपलब्ध कराया जा सके।

जाम मुक्त गाजियाबाद के लिए आपकी रणनीति क्या है?

जवाब- हमारा प्रयास है कि स्थानीय निवासियों को सुगम, सुरक्षित और निर्बाध यातायात उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए गाजियाबाद में प्रतिदिन लगभग 800 से 900 पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था में सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा कमिश्नरेट की ओर से क्रेन की भी व्यवस्था की गई है। सड़क पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों के कारण यातायात प्रभावित होता है। ऐसे वाहनों को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। हम चाहते हैं कि सड़क का इस्तेमाल सड़क के रूप में ही हो। अगर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है तो लोगों को सड़क पर वाहन खड़ा करने के बजाय निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करना चाहिए।

सवाल- जिले में सड़क हादसों और उनमें होने वाली मौतों को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस क्या विशेष कदम उठा रही है?

जवाब-माननीय डीजीपी सर के निर्देशन में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पूरे प्रदेश में ZFD और RTC जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गाजियाबाद में भी सबसे अधिक दुर्घटना वाले 10 स्थानों को चिन्हित कर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष सड़क हादसों में कमी आई है। इसके लिए केवल यातायात पुलिस ही नहीं, बल्कि दूसरे विभागों के साथ भी समन्वय किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, जल निगम, विद्युत विभाग सहित संबंधित विभागों के साथ मिलकर

दुर्घटना संभावित स्थानों की स्थिति को देखा जा रहा है। कई हादसे लोगों की लापरवाही के कारण भी होते हैं। इसलिए कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता भी जरूरी है। ITMS के माध्यम से चालान किए जा रहे हैं और मैनुअल कार्रवाई भी की जा रही है। हमारा उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना भी है।

सवाल- नाबालिग बच्चे, खासकर स्कूली छात्र, वाहन चलाते दिखाई देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है?

जवाब: नाबालिग बच्चों और उनके माता-पिता से मेरी स्पष्ट अपील है कि किसी भी परिस्थिति में नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति न दें। बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा स्कूल या किसी अन्य स्थान पर जा रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अन्य सुरक्षित माध्यम का उपयोग किया जाना चाहिए। माता-पिता को यह समझना होगा कि कुछ मिनट की सुविधा के लिए बच्चे को वाहन देना उसके जीवन को जोखिम में डाल सकता है। यातायात नियम केवल पुलिस से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए हैं।

सवाल- स्कूलों, बाजारों, आरडीसी, कचहरी और प्रमुख चौराहों पर पीक आवर्स के जाम से निपटने की क्या योजना है?

जवाब: हम लगातार ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पीक आवर्स में ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है। कचहरी क्षेत्र में कुछ दिन पहले बार एसोसिएशन के लोगों के साथ बातचीत की गई। बातचीत के बाद वहां वन-वे यातायात व्यवस्था लागू की गई, जिसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला है। इसी तरह घंटाघर और आरडीसी में क्रेन की व्यवस्था शुरू की गई है। सड़क पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को हटाया जा रहा है और उनका चालान भी किया जा रहा है। घंटाघर में रामलीला मैदान में पार्किंग की व्यवस्था शुरू की गई है। आरडीसी में भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। स्थानीय निवासियों और दुकानदारों से हमारी अपील है कि वे निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करें और सड़क पर वाहन खड़ा करके यातायात को बाधित न करें।

अवैध पार्किंग और सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम के लिए ट्रैफिक पुलिस दूसरे विभागों के साथ किस तरह काम कर रही है?

जवाब: अवैध पार्किंग और अतिक्रमण किसी एक विभाग की समस्या नहीं है। इसके समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय जरूरी है। हमारी कोशिश है कि सड़क की क्षमता का अधिकतम और व्यवस्थित उपयोग हो। जहां अवैध रूप से वाहन खड़े होते हैं वहां क्रेन के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के लिए भी संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है। ऑपरेशन क्लीन को भी और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास है, ताकि सड़कें अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग से मुक्त हो सकें।

सवाल- ई-रिक्शा और ऑटो के अव्यवस्थित संचालन तथा सड़क पर कहीं भी वाहन खड़ा करके सवारी भरने की समस्या पर क्या कार्रवाई हो रही है?

जवाब: ई-रिक्शा और ऑटो के कारण कई स्थानों पर यातायात का दबाव बढ़ता है। इस संबंध में व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना जरूरी है। जहां वाहन सड़क पर खड़ा करके सवारी बैठाते हैं या यातायात को बाधित करते हैं, वहां कार्रवाई की जाती है। हमारा उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक परिवहन भी चले और उसके कारण आम लोगों को जाम का

सामना भी न करना पड़े।

सवाल- त्योहारों का सीजन है और भीड़ काफी बढ़ेगी। अंबेडनगर रोड समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों पर क्या व्यवस्था रहेगी?

जवाब: त्योहारों को देखते हुए पुलिस की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। गाजियाबाद कमिश्नरेट की तरफ से कई ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां भीड़ अधिक रहती है, जहां बड़े मंदिर हैं, वहां पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है। स्थानीय पुलिस के साथ भी समन्वय किया जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि त्योहार के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आम लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे मौकों पर ट्रैफिक का दबाव सामान्य दिनों से काफी अधिक होता है। इसलिए पहले से प्लानिंग, पुलिस बल की तैनाती और जरूरत के अनुसार डायवर्जन की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। हाल में बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान भी ट्रैफिक पुलिस ने भारी संख्या में बल तैनात कर रूट मैनेजमेंट किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी गाजियाबाद में 900 से अधिक यातायात कर्मियों की तैनाती की गई थी, जिसमें NH-9 पर करीब 200 कर्मियों को लगाया गया था।

सवाल- गाजियाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?

जवाब: मैं स्थानीय निवासियों से अपील करना चाहूंगा कि वे यातायात नियमों का पालन करें। ट्रैफिक व्यवस्था केवल पुलिस के प्रयासों से बेहतर नहीं हो सकती। इसमें जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर लोग निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करें, गलत दिशा में वाहन न चलाएं, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, तेज गति से वाहन न चलाएं और सड़क पर नियमों का पालन करें तो यातायात व्यवस्था काफी बेहतर हो सकती है। हमारी कोशिश है कि गाजियाबाद में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले और लोगों को सुरक्षित, सरल और सुविधाजनक यातायात मिल सके।

आंकड़ों के आईने में गाजियाबाद की सड़क सुरक्षा

गाजियाबाद में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तकनीक, चालान और फील्ड पुलिसिंग पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन सड़क सुरक्षा की असली तस्वीर आंकड़ों से सामने आती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार संबंधित अवधि

में जिले में 665 सड़क हादसे दर्ज हुए। इन दुर्घटनाओं में 508 लोग घायल हुए, जबकि 254 लोगों की मौत हुई। यानी सड़क पर नियमों की अनदेखी अब भी एक गंभीर चुनौती है। दूसरी तरफ यातायात पुलिस की कार्रवाई का आंकड़ा भी काफी बड़ा है। इस अवधि में कुल 11,23,930 चालान किए गए।

किस नियम के उल्लंघन पर कितनी कार्रवाई?

कुल चालान-	**11,23,930**
हेलमेट उल्लंघन-	**करीब 77 हजार**
रॉन्ग साइड ड्राइविंग-	**करीब 73 हजार**
ओवर स्पीड-	**करीब 30 हजार**
नॉइज पॉल्यूशन-	**करीब 6 हजार**
एयर पॉल्यूशन-	**7,280**
सड़क हादसे-	**665**
घायल-	**508**
मृतक-	**254**

इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा चिंता हेलमेट और रॉन्ग साइड ड्राइविंग को लेकर है। सड़क पर गलत दिशा में वाहन चलाना न केवल स्वयं वाहन चालक के लिए बल्कि सामने से आने वाले दूसरे वाहन चालकों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। इसी तरह हेलमेट का इस्तेमाल न करना दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोट के जोखिम को बढ़ाता है। यही वजह है कि सड़क सुरक्षा की लड़ाई केवल चालान बढ़ाने तक सीमित नहीं हो सकती। जरूरत है कि दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान के साथ वहां सड़क की डिजाइन, संकेतक, रोशनी, स्पीड कंट्रोल और यातायात प्रबंधन की भी लगातार समीक्षा की जाए। स्कूल और कॉलेज स्तर पर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान, नाबालिगों को वाहन न देने के लिए अभिभावकों की जिम्मेदारी और सार्वजनिक परिवहन के बेहतर इस्तेमाल को भी इस अभियान का हिस्सा बनाना होगा।

आगे की राह: चालान से आगे सड़क सुरक्षा

गाजियाबाद की सड़कों की कहानी सिर्फ जाम की कहानी नहीं है। यह तेजी से बढ़ते शहर, बढ़ते वाहनों और बदलती जीवनशैली की कहानी भी है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के सामने चुनौती दोहरी है, एक तरफ यातायात को गतिशील रखना और दूसरी तरफ सड़क को सुरक्षित बनाना। ITMS और करीब 850 कैमरों की निगरानी व्यवस्था, क्रेन के माध्यम से अवैध पार्किंग पर कार्रवाई, वन-वे व्यवस्था, निर्धारित पार्किंग और दुर्घटना संभावित स्थानों पर विशेष अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि किसी भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ पुलिस से नहीं सुधरती। इसके लिए नागरिक अनुशासन, बेहतर सड़क ढांचा, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन का सुव्यवस्थित संचालन और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय जरूरी है।

वरुण कुमार सिंह की प्राथमिकताओं में भी यही बात प्रमुखता से दिखाई देती है, कार्रवाई के साथ जागरूकता और तकनीक के साथ जमीनी निरीक्षण। गाजियाबाद जैसे तेज रफ्तार शहर में शायद सबसे बड़ी जरूरत इसी संतुलन की है। क्योंकि आखिरकार ट्रैफिक मैनेजमेंट का अंतिम लक्ष्य सड़क पर ज्यादा गाड़ियां चलाना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित और समय पर उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। और सड़क सुरक्षा के आंकड़े एक बात बिल्कुल साफ कहते हैं, जाम से राहत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हर सफर सुरक्षित हो और हर व्यक्ति अपने घर वापस पहुंचे।

योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड: उपलब्धियां विपक्ष के सवाल और जनता का फैसला

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी राजनीति राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है। लगभग एक दशक के शासन के बाद अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, विपक्ष किन मुद्दों पर उसे घेर रहा है और जनता इन दोनों दावों को किस नजरिए से देख रही है।

सरकार की उपलब्धियां

भाजपा का दावा

योगी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि कानून-व्यवस्था को मानती है। सरकार का दावा है

हरेन्द्र शर्मा

कि संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क और भूमाफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम भाजपा की राजनीतिक पहचान का हिस्सा बन चुके हैं।

दूसरा बड़ा दावा आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, मेट्रो परियोजनाएं और औद्योगिक कॉरिडोर को सरकार विकास मॉडल के प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करती है।

तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र निवेश और उद्योग का है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से सरकार ने उत्तर प्रदेश को निवेश के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में भी भाजपा सरकार उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन वितरण, किसान सम्मान निधि

जनता क्या देख रही है?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता केवल आरोप और प्रत्यारोप नहीं देख रहा। वह अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय ले रहा है।
शहरी क्षेत्रों में सड़क, एक्सप्रेसवे, बिजली और सुरक्षा को लेकर सरकार के प्रति सकारात्मक धारणा दिखाई देती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं के बीच रोजगार, कृषि आय और शिक्षा से जुड़े प्रश्न अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। यही कारण है कि भाजपा का विकास और कानून-व्यवस्था का नैरेटिव तथा समाजवादी पार्टी का रोजगार और सामाजिक न्याय का नैरेटिव दोनों एक साथ राजनीतिक बहस का हिस्सा बने हुए हैं।

और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को अपनी उपलब्धियों में गिनाती है।

विपक्ष के सवालः अखिलेश यादव का हमला

समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियों के दावों को अधूरा बताते हैं। अखिलेश यादव लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि यदि निवेश आया है तो रोजगार कहां है? उनका आरोप है कि युवाओं को पर्याप्त नौकरियां नहीं मिलीं और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं ने युवाओं का विश्वास कमजोर किया है। समाजवादी पार्टी कानून-व्यवस्था के सरकारी दावों पर भी प्रश्न उठाती है। विपक्ष का तर्क है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध, सांप्रदायिक तनाव और स्थानीय स्तर की हिंसक घटनाएं अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं।

किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरता है। गन्ना भुगतान, फसलों की लागत और कृषि आय जैसे विषयों पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में अंतर है। अखिलेश यादव का एक प्रमुख आरोप यह भी है कि विकास परियोजनाओं का प्रचार अधिक और उनके सामाजिक-आर्थिक लाभ अपेक्षाकृत कम दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि विकास का वास्तविक मूल्यांकन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर होना चाहिए।

विश्लेषण

सच्चाई शायद दोनों राजनीतिक दावों के बीच कहीं मौजूद है। यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े निवेश और परियोजनाएं दिखाई देती हैं। कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर भी सरकार ने अपनी राजनीतिक पहचान बनाई है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, कृषि संकट और युवाओं की आकांक्षाएं अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई हैं। भाजपा के सामने चुनौती उपलब्धियों को रोजगार और जीवन स्तर में प्रत्यक्ष सुधार में बदलने की है, जबकि समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती केवल आलोचना करने के बजाय एक विश्वसनीय वैकल्पिक विकास मॉडल प्रस्तुत करने की है।

अंततः उत्तर प्रदेश की राजनीति में अंतिम फैसला न सरकार के दावों से होगा और न विपक्ष के आरोपों से। फैसला उस मतदाता के अनुभव से होगा जो सड़क भी चाहता है, सुरक्षा भी चाहता है और अपने बच्चों के लिए रोजगार और बेहतर भविष्य भी चाहता है।

सभाओं की गूंज, बयानों की धार और मुद्दों की तलाश

उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर चुनावी तैयारी के दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक चेहरे–मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, अपना दल (एस) की नेता अनुप्रिया पटेल और सुभासपा के ओमप्रकाश राजभर–लगातार जनसभाओं, राजनीतिक बयानों और संगठनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपने-अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने में जुटे हैं।

देश की सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र है। यहां बनने वाले राजनीतिक

रवि जैन

समीकरण अक्सर दिल्ली की सत्ता की दिशा तय करते हैं।

योगी आदित्यनाथः विकास और राष्ट्रवाद का मॉडल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति आज भाजपा के सबसे बड़े राजनीतिक नैरेटिव पर आधारित है–कानून-व्यवस्था, विकास और राष्ट्रवाद।

योगी सरकार एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश, धार्मिक पर्यटन और माफिया विरोधी कार्रवाई को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर रही है। भाजपा का मानना है कि जातीय राजनीति से ऊपर उठकर 'विकास और सुशासन' का मुद्दा मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है।

अखिलेश यादवः युवाओं और सामाजिक न्याय की राजनीति

अखिलेश यादव भाजपा के विकास मॉडल पर सबसे मुखर सवाल उठा रहे हैं। उनकी सभाओं में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और पिछड़े वर्गों के अधिकार प्रमुख विषय रहते हैं।

समाजवादी पार्टी का प्रयास यादव-मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़कर युवाओं, पिछड़ों और

ग्रामीण मतदाताओं को जोड़ने का है। अखिलेश यादव खुद को भाजपा के सामने मुख्य वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।

मायावती: शांत राजनीति, लेकिन स्थायी प्रभाव

मायावती की राजनीतिक शैली अन्य नेताओं से अलग है। वे कम रैलियां करती हैं, लेकिन उनके बयान दलित राजनीति के केंद्र में बने रहते हैं। बसपा की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित वोट बैंक है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में पार्टी का चुनावी प्रभाव कम हुआ है, फिर भी उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग आज भी मायावती को सम्मान और भरोसे के साथ देखता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बसपा अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को पुनर्गठित करने में सफल होती है, तो वह कई सीटों पर चुनावी समीकरण बदल सकती है।

जयंत चौधरी: पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई उम्मीद

जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव विशेष रूप से जाट किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देता है। जयंत चौधरी ने किसान आंदोलन के बाद अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत किया। वर्तमान में भाजपा के साथ उनकी निकटता ने उन्हें सत्ता और संगठन दोनों का लाभ दिया है। हालांकि उनके सामने चुनौती यह है कि वे अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखें और केवल गठबंधन की राजनीति तक सीमित न रह जाएं।

अनुप्रिया पटेल: कुर्मी राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा

अनुप्रिया पटेल पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में कुर्मी तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बीच प्रभाव रखती हैं। भाजपा के सहयोगी दल के रूप में उनकी भूमिका भाजपा के सामाजिक विस्तार की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुप्रिया पटेल लगातार पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को उठाती रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका महत्व सीटों से अधिक सामाजिक समीकरणों के कारण है।

ओमप्रकाश राजभर: पिछड़ों की राजनीति की मुखर आवाज

ओमप्रकाश राजभर पूर्वांचल में गैर-यादव पिछड़े वर्गों की राजनीति के महत्वपूर्ण नेता हैं। वे आरक्षण, सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी के मुद्दों को लगातार उठाते हैं। राजभर का राजनीतिक प्रभाव भले सीमित भौगोलिक क्षेत्र में हो, लेकिन कई चुनावी सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक बन जाती है।

कांग्रेस: इतिहास की विरासत, भविष्य की तलाश

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी भी पुनर्जीवन की प्रक्रिया में है। कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस आज संगठनात्मक कमजोरी और नेतृत्व के स्थानीय अभाव से जूझ रही है। हालांकि दलित, अल्पसंख्यक, महिला और युवा मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल पार्टी भाजपा और समाजवादी पार्टी के मुकाबले तीसरे या चौथे विकल्प के रूप में दिखाई देती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह खुद को केवल गठबंधन सहयोगी नहीं बल्कि स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करे।

असली मुद्दे क्या हैं?

नेताओं की सभाओं और बयानों के बीच उत्तर प्रदेश का मतदाता रोजगार, कृषि आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी नजर रखे हुए है। शहरी मतदाता विकास और निवेश की बात करता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आय, सिंचाई और रोजगार की चिंता प्रमुख है। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र में अवसर और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुके हैं।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश की राजनीति आज बहुध्रुवीय दिखाई देती है। भाजपा सत्ता और विकास के भरोसे चुनावी बढ़त बनाए रखना चाहती है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में सत्ता को चुनौती दे रही है। बसपा अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल और ओमप्रकाश राजभर जैसे नेता सामाजिक समीकरणों को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपनी पुरानी राजनीतिक विरासत को नए दौर में पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इन सभी राजनीतिक प्रयासों के बीच अंतिम शक्ति मतदाता के हाथ में है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां जनता अक्सर आखिरी समय में ऐसा फैसला करती है जो पूरे देश की राजनीति को नई दिशा दे देता है।

महंगाई, कमजोर मानसून और अमेरिकी शुल्क ने बढ़ाई चिंता

जयंतीलाल भंडारी अपने इस लेख में बता रहे है कि रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.0 फीसद कर दिया है। जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 6.7 फीसद कर दिया गया है।

संजय बैंसला

देश के आर्थिक परिदृश्य में बहुआयामी चुनौतियों का दायरा बढ़ता जा रहा है। ईंधन का संकट अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि कमजोर मानसून, बढ़ती महंगाई और अमेरिकी शुल्क संबंधी नई मुश्किलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद देश में महंगाई, आर्थिक स्थिति और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि से जुड़ी तस्वीर पेश की है।

रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.0 फीसद कर दिया है। जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 6.7 फीसद कर दिया गया है। खास तौर से रेपो रेट (वह ब्याज दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं) को लगातार चौथी बार 5.25 फीसद के स्तर पर यथावत रखा गया है। आरबीआइ ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में अल नीनो के प्रभाव, मानसून के कमजोर रहने और पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से खाने-पीने की वस्तुएं और ईंधन महंगे हो सकते हैं।

निस्संदेह इस समय पश्चिम एशिया संकट और अमेरिका की आर्थिक नीतियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर चौतरफा दबाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए-नए आर्थिक और व्यापारिक संरक्षणवादी कदमों से भारत के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से अमेरिका के व्यापार, कृषि, बौद्धिक संपदा और श्रम बाजार से जुड़ी नीतिगत बदलावों के कारण उत्पन्न हुई है। आयात पर अतिरिक्त शुल्क लागू करने और नीतियों को कठोर बनाने से भारतीय निर्यात प्रभावित हो रहा है।

इसके साथ ही अमेरिका अपने कृषि और दुग्ध उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच की मांग कर रहा है। अमेरिका की वीजा नीतियों में कड़ाई और शुल्क वृद्धि से भारतीय सूचना-प्रौद्योगिकी कंपनियों एवं पेशेवरों के समक्ष अनिश्चितता पैदा हो रही है। वीजा प्राथमिकताओं में बदलाव और प्रशासनिक बाधाओं के कारण कुशल प्रतिभाओं की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है, जिससे सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

हाल ही में अमेरिकी संसद के उच्च सदन (सीनेट) ने रूस से कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों के खिलाफ एक कठोर विधेयक पारित किया है। यदि यह विधेयक निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) से मंजूर हो जाता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत और चीन जैसे प्रमुख तेल खरीदार देशों पर सौ फीसद तक का शुल्क लगाने का अधिकार मिल जाएगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य रूस और ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना तथा उनके युद्ध प्रयासों के वित्तीय स्रोतों को सीमित करना है।

इसमें दोराय नहीं है कि अमेरिका की ओर से रूस पर संभावित नए और सख्त प्रतिबंध भारतीय बाजार के लिए एक बड़ा वैश्विक जोखिम बन सकते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी है, क्योंकि रूस सस्ते कच्चे तेल का प्रमुख स्रोत है। पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने इस वर्ष जुलाई में लगातार दूसरे महीने रूस से कच्चे तेल का रिकॉर्ड आयात किया है। 'सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर' के अनुसार, भारतीय कंपनियों ने जुलाई में 5.5 अरब यूरो (28 लाख बैरल प्रतिदिन) का रूसी कच्चा तेल खरीदा।

यह भारत के कुल पचास लाख बैरल प्रतिदिन के आयात का पचपन फीसद से अधिक है। ऐसे में नए प्रतिबंधों के कारण रूस से तेल आयात में रुकावट आती है, तो इससे घरेलू कंपनियों की लागत

और देश का कुल आयात खर्च बढ़ सकता है।

हाल में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने एच-1बी और एल-1 वीजा के विस्तार आवेदनों पर अतिरिक्त शुल्क लागू करने की घोषणा की है। इस वर्ष नौ सितंबर से लागू होने वाले इस नियम के तहत एच-1बी वीजा विस्तार के लिए 4,000 डॉलर (लगभग 3.68 लाख रुपए) और एल-1 विस्तार के लिए 4,500 डॉलर (लगभग 4.2 लाख रुपए) शुल्क देना होगा। यह नियम पचास या उससे अधिक कर्मचारियों वाली उन बड़ी कंपनियों पर लागू होगा, जिनके पचास फीसद से अधिक कर्मचारी इन्हीं वीजा के आधार पर नियुक्त हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में पिछले माह अमेरिकी संसद में कार्य वीजा पर तीन साल तक रोक लगाने संबंधी एक नया और सख्त विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक के लागू होने से तकनीकी क्षेत्र के भारतीय पेशेवरों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। नए प्रस्तावों में एक लाख डॉलर (लगभग 85 से 95 लाख रुपए) तक का भारी-भरकम शुल्क और कठोर न्यूनतम वेतन मानदंड शामिल हैं। इसके अलावा वीजा धारकों के आश्रितों और परिजनों पर भी कई पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव है।

अमेरिका ने पिछले माह भारत समेत 17 देशों से आने वाले सामान पर दस फीसद का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका ने यह कदम उन देशों के खिलाफ उठाया है, जिनके उत्पादों के निर्माण में जबरन मजदूरी की शिकायतें मिली थीं। शुरूआत में भारत पर 12.5 फीसद शुल्क लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन भारत की ओर से अपनी विदेश व्यापार नीति में सुधार करने पर इसे घटाकर दस फीसद कर दिया गया।

> जीडीपी की वृद्धि का अनुमान 6.7 फीसद कर दिया गया है। खास तौर से रेपो रेट (वह ब्याज दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं) को लगातार चौथी बार 5.25 फीसद के स्तर पर यथावत रखा गया है।

इसके अलावा अमेरिका ने जेनेरिक दवाओं के आयात पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत अगस्त, 2028 से 31 जुलाई 2029 तक दवाओं के मूल्य पर सौ फीसद और उसके बाद इसे बढ़ाकर दो सौ फीसद कर दिया जाएगा। ऐसे में अब भारत को अमेरिका के साथ आगे बढ़ रहे द्विपक्षीय व्यापार समझौते में अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्रति अत्यंत सतर्क रहना होगा। इन आर्थिक और व्यापारिक चुनौतियों के बीच एशियाई विकास बैंक की ओर से हाल में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशियाई संकट और लॉजिस्टिक खर्च में बढ़ोतरी का भारत की विकास दर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। रिपोर्ट में भारत की वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूर्व में निर्धारित 6.9 फीसद की विकास दर को घटाकर 6.6 फीसद कर दिया गया है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.4 फीसद कर दिया है। जबकि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7 फीसद की शानदार दर से वृद्धि दर्ज की थी।

हालांकि इस समय भारत आपूर्ति चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से बेहतर स्थिति में है, फिर भी चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर को सात फीसद तक ले जाने के लिए रणनीति पूर्वक नए आर्थिक उपायों के साथ आगे बढ़ना होगा। सरकार को 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के फार्मूले को और बेहतर ढंग से उपयोग में लाना होगा। केंद्रीय बैंक को अब महंगाई पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ विकास की गति को थमने से बचाना होगा। आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने के लिए सरकार को अपने पूंजीगत व्यय को लक्ष्य के अनुरूप तेजी से कारगर बनाना होगा।

आखिर दिल्ली क्यों रहती है आतंकियों के निशाने पर ?

चरण सिंह

आपको पता होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर यानी राष्ट्रीय पर्वों दिल्ली अक्सर पाक परस्त आतंकियों के निशाने पर रहती है ! ऐसा खुफिया जानकारियों से भी पता चलता है। ऐसा इसलिए कि नई दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक, संवैधानिक और प्रतीकात्मक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। चूंकि राष्ट्रीय पर्व–15 अगस्त तथा 26 जनवरी–आतंकियों के लिए इसी प्रतीकात्मक महत्व को भुनाने और इसमें भागीदारी जताने वालों के बीच अधिकतम भयावह माहौल पैदा करने का षड्यंत्र रचा जाता है, इसलिए खुफिया व सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो जाती हैं।

दरअसल, इस अहम मौके पर जगह जगह उमड़ने वाली भीड़ के बीच आतंकियों द्वारा अपने नापाक इरादों को पूरे करने के अवसर के रूप में देखा जाता है और इसी उद्देश्य से वो अमन-चैन के दुश्मन बन जाते हैं। भला हो एनआईए, खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस का जो समय रहते ही उनके नापाक इरादों को ध्वस्त कर देती हैं। इस समय यह सवाल और गंभीर है, क्योंकि 13 अगस्त 2026 को सामने आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने नवंबर 2025 के Red Fort आतंकी हमले को AQIS (Al-Qaeda in the Indian Subcontinent) से आधिकारिक रूप से जोड़ा है।

आइए, अब उन वजहों की चर्चा करते हैं जिनकी वजह से दिल्ली आतंकियों के निशाने पर रहती है:-

पहला, दिल्ली पर हमला यानी पूरे भारत को संदेशः आतंकी संगठन केवल जान-माल का नुकसान नहीं चाहते, बल्कि उनका असली लक्ष्य अक्सर भय, प्रचार और राजनीतिक संदेश पैदा करना होता है। चूंकि दिल्ली में संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट, मंत्रालय, विदेशी दूतावास और राष्ट्रीय स्मारक जैसे संस्थान हैं। इसलिए यहां घटी हुई छोटी सी घटना का भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है।

दूसरा, राष्ट्रीय पर्वों पर प्रतीकात्मक मूल्य बढ़ जाता है कई गुनाः 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह–ये दोनों भारत की राजकीय संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता

के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रतीक हैं। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां वर्षों से मानती रही हैं कि Independence Day समारोह आतंकियों और उग्रवादी संगठनों के लिए "attractive target" हो सकते हैं, यानी आतंकियों की गणित कुछ ऐसी होती हैः सामान्य दिन का हमला स्थानीय/क्षेत्रीय खबर लेकिन राष्ट्रीय पर्व के दिन दिल्ली में हमला अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां + राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक प्रभाव + सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल।

तीसरा, भीड़ और VVIP मौजूदगीः राष्ट्रीय समारोहों में हजारों लोग, VVIP/VIP सुरक्षा बल, मीडिया और देश-विदेश के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। 15 अगस्त 2026 के Red Fort समारोह के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था बेहद व्यापक है और दिल्ली में प्रवेश, यातायात, मेट्रो तथा संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। आतंकी संगठनों के लिए भीड़ का अर्थ होता है कि एक छोटी कोशिश भी बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी पैदा कर सकती है।

चौथा, लाल किला स्वयं एक असाधारण प्रतीक हैः लाल किला केवल ऐतिहासिक इमारत नहीं है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का तिरंगा फहराना उसे आधुनिक भारतीय राष्ट्र-राज्य के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में बदल देता है।

इसीलिए Red Fort पहले भी आतंकवादी लक्ष्य रहा है। दिसंबर 2000 में वहां आतंकी हमला हुआ था। और नवंबर 2025 का हमला इस खतरे की आधुनिक अभिव्यक्ति था। अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में AQIS का नाम सामने आना इस पूरे मामले को और गंभीर बनाता है।

पांचवां, दिल्ली की एक और कमजोरी—बहुत बड़ा और खुला महानगरीय क्षेत्रः यह केवल Red Fort की सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि दिल्ली-ठउफ में रेलवे स्टेशन, मेट्रो नेटवर्क, बाजार, बस अड्डे, धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, सरकारी संस्थान, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान और बहुत बड़ी संख्या में हैं। इसलिए किसी आतंकी संगठन के लिए केवल मुख्य समारोह को निशाना बनाना ही जरूरी नहीं होता। समारोह के आसपास किसी दूसरे संवेदनशील स्थान पर घटना करके भी भय का वातावरण बनाया जा सकता है। इसी कारण इस बार रेलवे हब और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है।

छठा, राष्ट्रीय पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था पहले से दिखाई देती हैः यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर सुरक्षा सबसे ज्यादा होती है—लेकिन उसी कारण सुरक्षा की तैनाती, रास्ते, समारोह का स्थान और समय जैसी बहुत-सी चीजें सार्वजनिक रूप से ज्ञात भी होती हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां केवल समारोह स्थल की सुरक्षा नहीं करतीं, बल्कि पूरे शहर में layered security बनाती हैं। इस साल दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर पुलिस बल, CCTV, ड्रोन, वाहन जांच और अन्य निगरानी उपाय बढ़ाए हैं।

सातवां, असली खतरा सिर्फ 'बड़ा हमला' नहीं हैः आज आतंकवाद की रणनीति भी बदल रही है। बड़े संगठित समूहों के बजाय छोटे, बिखरे हुए सेल, स्थानीय मददगार, डिजिटल संपर्क और कम लागत वाले हमले ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। UN की हालिया रिपोर्ट में भी AQIS के बारे में छोटे और बिखरे हुए नेटवर्क तथा क्षेत्रीय लॉजिस्टिक/वित्तीय नेटवर्क की चिंता व्यक्त की गई है। इसका मतलब है कि केवल Red Fort की अभेद्य सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। Intelligence + cyber monitoring + financial tracking + border intelligence + local policing + community intelligence—इन सभी को जोड़ना पड़ेगा।

लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर यह कहना सही नहीं होगा कि 'हर 15 अगस्त या 26 जनवरी को दिल्ली पर हमला होने वाला है।' राष्ट्रीय पर्वों के आसपास सुरक्षा एजेंसियों द्वारा खतरे की आशंका को गंभीरता से लेना एक precautionary security doctrine है। 2026 में भी हाई अलर्ट और व्यापक सुरक्षा व्यवस्था इसी सावधानी का हिस्सा है। लेकिन नवंबर 2025 के Red Fort हमले और अब वठ की AQIS attribution के बाद यह जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली के प्रतीकात्मक स्थलों को लेकर आतंकवादी संगठनों की रुचि को केवल काल्पनिक खतरा मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।सुरक्षा उत्पाद और सेवाएं

समझिए सबसे बड़ा सवाल और जानिए जवाबः मेरे विचार से असली प्रश्न यह नहीं है कि 'आतंकी दिल्ली को क्यों चुनते हैं?' बल्कि असली प्रश्न यह है कि- क्या भारत की राजधानी को केवल राष्ट्रीय पर्वों पर ही नहीं बल्कि वर्ष के 365 दिनों में ऐसी बहुस्तरीय सुरक्षा मिल रही है जिसमें आतंकियों की योजना बनने से पहले ही उसका पता चल जाए? क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हमला होने के बाद हमलावर पकड़ना नहीं, बल्कि हमला होने से पहले साजिश को तोड़ देना है।

विरोध प्रदर्शन करें पर ना हो सीमाओं का अतिक्रमण

क्या कभी सोचा है कि हमारे प्रदर्शन से प्रदर्शन वाले शहरवासियों को कितना प्रभावित करता है। प्रदर्शन वाले शहर का कहीं ज्यादा तो कहीं कम यातायात प्रभावित हो जाता है। निजी व सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बाधित हो जाती है। मरीजों व जरूरी काम वालों को बीच रास्ते अटकना पड़ जाता है।

आये दिन होने वाले प्रदर्शनों के चलते सामान्य जनजीवन को बंधक बना देने की प्रवृति पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रदर्शनों के कारण कई बार तो जीवन मरण तक के हालात पैदा हो जाते हैं। अन्य सब कारणों और परिणामों को थोड़ी देर के लिए अलग कर भी दिया जाएं तो भी हालात यहां तक हो जाते हैं कि यातायात प्रभावित होने से तत्काल मेडिकल रिलिफ की आवश्यकता वाले बीमारों तक का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने, अपनी बात रखने और अपना विरोध अंकित कराने का सबको अधिकार है। केई गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी होना चाहिए

राहुल अग्रवाल

पर इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बात कहने के चक्कर में दूसरों को अपने सामान्य नागरिक अधिकारों से वंचित कर दें। विरोध प्रदर्शन के साथ ही साथ दायित्व भी होता है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का विरोध भी नहीं होता पर कब इस तरह के प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं और कानून व्यवस्था के गंभीर हालात हो जाते हैं इसका खामियाजा प्रदर्शनकारियों को नहीं अपितु प्रशासन और आमजन को भुगतना पड़ता है। सीजीपी के हालिया प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में जो हालात बने और जयपुर में पिछले दिनों सीजीपी द्वारा स्कूल प्रकरण को लेकर ग्रामवासियों और सीजीपी लोगों के साथ हालात बने यह अपने आप में गंभीर हो जाता है। रांची और देश के अन्य स्थानों के प्रदर्शनों को भी इसी संदर्भ में देखना होगा। शहर की सामान्य व्यवस्था को ही प्रभावित करने वाले स्थानों पर प्रदर्शन स्वीकृति पर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण हो जाती है कि शहर के बीच प्रदर्शन की अनुमति क्यों कर दी जानी चाहिए। दरअसल सीजीपी द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किये गये और यह प्रदर्शन देखते देखते हिंसक हो गया। इसके बाद

प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन और पक्ष प्रतिपक्ष द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल जाता है पर मूल कारण को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे पहले 2017-18 में जलकट्ठू घटना के संदर्भ में गठित न्यायमूर्ति राजेश्वरन आयोग की सिफारिशें भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

लोकतंत्र में विरोध अधिकार हो सकता है पर विरोध का एक तरीका होता है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का सबको अधिकार है पर अपने विरोध प्रदर्शन के चक्कर में अन्य और वह भी आमनागरिकों का जनजीवन प्रभावित करने का किसी को अधिकार नहीं हो सकता। विरोध के चलते कानून हाथ में लेना या क्षेत्राधिकार से बाहर जाना एक सभ्य समाज और सभ्य नागरिक की पहचान नहीं हो सकती। सरकारी या निजी संपत्ती को नुकसान पहुंचाना या कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता।एक बात यह भी समझनी होगी कि पुलिस प्रशासन भी आखिर आदमी है और देखा जाएं तो उनका मरण दोनों तरफ से हो जाता है। यदि प्रदर्शनकारियों को एक सीमा से अधिक बढ़ने पर रोके नहीं तो प्रशासन की विफलता कहने में कोई देरी नहीं लगाता, यहां तक कि प्रशासन की इंटेलिजेंस फैलियर जैसे आरोप लग जाते हैं। प्रदर्शन के हिंसक होने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की आलोचना आम हो जाती है पर जब कई बार प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रदर्शन के दौरान बेरिकेड़ तोड़ने, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और निरपराध आमजन को निशाने पर लेने लगते हैं तो एक बात साफ हो जानी चाहिए कि फिर प्रशासन गुलाब के फूल देकर तो प्रदर्शन को नियंत्रित नहीं कर सकता हांलाकि प्रशासन को भी संयम बरतते हुए ही कदम उठाने चाहिए। दरअसल तस्वीर के दोनों पक्षों को देखना होगा। यदि प्रदर्शन सामान्य होता है और अनुमति प्राप्त शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो तो उस पर पुलिस प्रशासन की सख्ती को किसी भी हालात में स्वीकारा नहीं जा सकता पर प्रदर्शनकारियों द्वारा लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है तो उस पर प्रशासन को भी कानूनी दायरें में रहते हुए कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी।

अब जयपुर के स्कूल की घटना का विश्लेषण करें तो हालात की ओर ध्यान दिलाना एक उचित कदम हो सकता है पर स्कूल या किसी भी सरकारी-गैरसरकारी संस्थान का निरीक्षण का अधिकार किस कानून ने दे दिया है।एक सीमा तक प्रदर्शन आपका अधिकार हो सकता है पर प्रदर्शन से माहौल को तनावपूर्ण और द्वेषतापूर्ण बनाने की किसी भी व्यवस्था में अनुमति नहीं दी जा सकती और नहीं दी भी जानी चाहिए। प्रशासन, प्रदर्शनकारियों और आमजन को अपनी सीमाओं को समझना होगा। सुर्खियों में बनने के लिए कदम उठाना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

क्या कभी सोचा है कि हमारे प्रदर्शन से प्रदर्शन वाले शहरवासियों को कितना प्रभावित करता है। प्रदर्शन वाले शहर का कहीं ज्यादा तो कहीं कम यातायात प्रभावित हो जाता है। निजी व सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बाधित हो जाती है। मरीजों व जरुरी काम वालों को बीच रास्ते अटकना पड़ जाता है। नौकरीपेशा या धंधे पर जाने वाले रास्ते में ही अटक जाते है। दैनिक काम के आधार पर रोजी रोटी कमाने वालों की मजदूरी अटक जाती है। शहर की सभी तरह की सप्लाई चैन बाधित हो जाती है। पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाये रखने के लिए व्यस्त हो जाता है तो लोगों में असुरक्षा की भावना बनती है और बाहर निकलने से पहले सोचने को मजबूर हो जाते हैं। और अब तो प्रशासन द्वारा ऐसे शहरों में इंटरनेट बंद करने तक का निर्णय कर लिया जाता है जिससे सामान्य गतिविधियां, बैंकिंग व्यवस्था, सूचनाओं का आदान-प्रदान और पढ़ाई-लिखाई तक पर असर पड़ता है। ऐसे में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित महाजन की यह टिप्पणी कि शहर को बेवजह बंधक बनाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है।

प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। पहले तो प्रशासन को भी चाहिए कि प्रदर्शन आदि के लिए ऐसा स्थान निर्धारित हो जहां से सामान्य जनजीवन किसी तरह से प्रभावित ना हो सके। आम जन, शहरी यातायात, शहर का दैनिक जनजीवन किसी तरह से प्रभावित ना हो। ऐसी व्यवस्था हो जिससे प्रदर्शनकारियों की बात वे जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाई जा सके। प्रदर्शनकारियों को भी प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। असामाजिक तत्वों को किसी तरह का मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए। जब किसी प्रदर्शन के दौरान हिंसा या गलत गतिविधियां होने लगती है और व्यवस्था हाथों से निकलने लगती है व प्रशासन द्वारा सख्ती होती है तो यह सामान्य जबाव होता है कि हिंसा या हालात बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्व उनमें से नहीं थे पर ऐसा कहने मात्र से जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय व न्यायालयों द्वारा पूर्व में भी दी गई टिप्पणियों को गंभीरता से प्रदर्शनकताओं और प्रशासन दोनों को समझना होगा व दोषारोपण के नाम पर जिम्मेदारी से भागने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती। अपनी बात कहने के अधिकार के साथ दूसरों के मौलिक अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने या सीमाओं को लांघने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता।

ऊंची इमारतें या नागरिक का आत्मसम्मान: क्या है देश की सच्ची प्रगति का पैमाना?

सचिन तोमर

किसी भी देश की प्रगति का आकलन केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों या बड़ी-बड़ी योजनाओं से नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी सामान्य नागरिक के भीतर आत्मसम्मान और गरिमा का भाव खोज पाते हैं, तभी यह कहा जा सकता है कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास के केंद्र में अगर मनुष्य की प्रतिष्ठा हो, तो वह प्रगति निश्चित ही सार्थक कही जा सकती है।

आखिर देश के प्रतिनिधियों का सबसे महत्त्वपूर्ण दायित्व अपने नागरिकों की सेवा करना और उनके सम्मान की रक्षा करना ही तो होता है। अन्य योजनाओं का मूल्य भी अक्सर इसी बात से तय किया जा सकता है कि वे आम लोगों के जीवन और गरिमा को कितना बेहतर बना पाती हैं।

एक लंबी यात्रा के दौरान किसी रेस्तरां में अगर वाजिब दामों पर स्वच्छ भोजन हो, बैठने की व्यवस्था साफ-सुथरी हो और शौचालयों की नियमित सफाई जैसे इंतजाम के बीच अगर संपन्न वर्ग के साथ और समान स्तर पर आम लोगों के लिए भी जगह हो, तो थोड़ी हैरानी होती है। ऐसे दृश्य कम ही देखने में आते हैं।

गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति को जीवन में कहीं न कहीं पहुंचना होता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भी एक जैसी ही होती हैं। स्वच्छ भोजन, सुरक्षित पेयजल, साफ शौचालय और कुछ देर आराम से बैठने की जगह कोई विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि एक सम्मानपूर्ण जीवन की बुनियादी शर्तें हैं।

अक्सर हम विकास को बड़ी परियोजनाओं और आंकड़ों में खोजते हैं, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप उन छोटी-छोटी सुविधाओं में दिखाई देता है, जिनका उपयोग हर नागरिक करता है। एक साफ बस अड्डा, एक सुरक्षित सार्वजनिक शौचालय, सरकारी अस्पताल में मानवीय व्यवहार या किसी कार्यालय में बिना अपमान के अपना काम कर पाने का अनुभव- ये सब मिलकर व्यक्ति के भीतर यह विश्वास पैदा करते हैं कि वह इस देश में केवल एक संख्या नहीं, बल्कि अधिकारों और गरिमा के साथ जीने वाला नागरिक है। आत्मसम्मान का यही भाव नागरिक और राष्ट्र के बीच विश्वास का आधार बनाता है।

जब किसी व्यक्ति को केवल इसलिए गंदे शौचालय, दूषित पेयजल, अस्वास्थ्यकर वातावरण स्वीकार करने के लिए मजबूर होना

गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति को जीवन में कहीं न कहीं पहुंचना होता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भी एक जैसी ही होती हैं। स्वच्छ भोजन, सुरक्षित पेयजल, साफ शौचालय और कुछ देर आराम से बैठने की जगह कोई विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि एक सम्मानपूर्ण जीवन की बुनियादी शर्तें हैं।

पड़े कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है, तो यह केवल उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का भी अपमान है, जिसने अपने नागरिकों की गरिमा की रक्षा को प्राथमिकता नहीं दी। जब मनुष्य की सारी ऊर्जा केवल बुनियादी आवश्यकताओं को जुटाने में ही खर्च होने लगे, तब उसके भीतर नागरिक चेतना, सामाजिक जिम्मेदारियों और बेहतर जीवन के सपनों के लिए बहुत कम स्थान बचता है।

ऐसे में उससे उच्च आदर्शों और 'सिविक सेंस' या नागरिक चेतना की अपेक्षा करना भी कुछ हद तक बेमानी प्रतीत होता है। जिसके पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का ही अभाव हो, उससे केवल उपदेशों के सहारे बेहतर नागरिक बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती। यही बात कामकाजी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के साथ होने वाले व्यवहार पर भी लागू होती है।

उनके प्रति कठोर और अपमानजनक रवैया केवल व्यक्तिगत संवेदनहीनता का परिणाम नहीं है, बल्कि कई बार उन नियमों और व्यवस्थाओं के अभाव का भी परिणाम है, जो उनके अधिकारों और हितों की रक्षा कर सके। बुनियादी कामगार, जिन पर देश की मजबूत नींव निर्भर करती है, उनका सम्मान और गरिमा भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी समाज के संपन्न वर्ग की।

सुविधाओं की दृष्टि से यही बात वृद्धजनों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं पर भी लागू होती है। परेशानियों के बीच जीवन को सहज बनाए रखने का पूरा दायित्व केवल व्यक्ति के कंधों पर नहीं होना चाहिए। उसके आसपास के वातावरण में भी गर्मजोशी, सहानुभूति और सहायता के विकल्प स्वाभाविक रूप से मौजूद होने चाहिए। किसी समाज की संवेदनशीलता का आकलन इस बात से भी होता है कि वह अपने सबसे कमजोर और सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता रखने वाले लोगों के लिए कितना सहज और मानवीय वातावरण तैयार कर पाता है।

शायद यही कारण है कि विकसित समाजों की पहचान केवल उनकी समृद्धि से नहीं, बल्कि उनकी संवेदनशीलता से भी होती है। वहां सुविधाओं की गुणवत्ता व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के अनुसार नहीं बदलती। एक सामान्य नागरिक के लिए भी वही स्वच्छता, वही व्यवस्था और वही शालीन व्यवहार सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

विलासिता और भव्यता से जुड़े काम तो सेठ-साहूकार हमेशा से करते आए हैं। किसी राष्ट्र की वास्तविक पहचान भव्य आयोजनों से नहीं बनती, बल्कि उन साधारण स्थानों से बनती है, जहां एक सामान्य नागरिक बिना किसी हीन भावना के बैठ सके, स्वच्छ पानी पी सके, सम्मानपूर्वक शौचालय का उपयोग कर सके, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके और यह महसूस कर सके कि इस देश में उसकी प्रतिष्ठा का मूल्य उसकी जेब से नहीं, बल्कि उसके नागरिक होने से तय होता है।

देश भले ही विकास की धीमी रफ्तार पर हो, पर उसके प्रयासों का सही दिशा में होना आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराना किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आखिर किसी राष्ट्र की सफलता का वास्तविक पैमाना उसकी संपन्नता नहीं, बल्कि वह आदर है, जिसे वहां का सबसे साधारण व्यक्ति भी अपने हिस्से का अधिकार समझकर महसूस करता है।

एक ओर जीवन हमसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, तो दूसरी तरफ हमारे भीतर बहुत हठी ऐसा कुछ है, जो बार-बार मुड़ कर पीछे देखने का आग्रह करता है। अतीत की सड़कों पर सैर करने के लिए कहता है। पुराने एल्बम देखना, बचपन के दोस्तों के बारे में बातें करना, बचपन में सुने गीत गुनगुनाना। कुल मिला कर अतीत की एक रूमानी छवि रचना और फिर उसका महिमामंडन करना- यह मन की गहरी आदतों में शामिल है।

भाजपा का मिशन 2027

मोदी-योगी ने बनाई रणनीति

दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड में डालते हुए नई नियुक्तियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने छह संगठनात्मक क्षेत्रों और विभिन्न मोर्चों के प्रभारियों की घोषणा की है। नई टीम में करीब 60 फीसदी नए चेहरों को जगह दी गई है।

पीएम मोदी और सीएम योगी ने बनाया बड़ा प्लान कई BJP विधायकों के टिकट पर संकट!

ललित कुमार

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के बाद प्रदेश की सियासत में चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने इसे सुशासन के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली मुलाकात बताया। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को केवल शिष्टाचार भेंट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है।

भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड में डाला

शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड में डालते हुए नई नियुक्तियों का ऐलान किया है। पार्टी ने छह संगठनात्मक क्षेत्रों और विभिन्न मोर्चों के प्रभारियों की घोषणा की है। नई टीम में करीब 60 फीसदी नए चेहरों को जगह दिए जाने की बात सामने आई है।

इससे संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा मिशन 2027 को केवल राजनीतिक नारे तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक संगठन को मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है।

क्षेत्रवार जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव

नई संगठनात्मक व्यवस्था के तहत प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल को अवध, अभिजात मिश्रा को गोरखपुर, प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह को काशी और गीता शाक्य को ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, राम प्रताप चौहान को पश्चिमी क्षेत्र और शंकर लोधी को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है।

भाजपा ने इस बार प्रदेश महामंत्रियों की संख्या भी सात से बढ़ाकर आठ कर दी है। विभिन्न मोर्चों

की जिम्मेदारियां भी नए नेताओं को सौंपी गई हैं। पार्टी की कोशिश युवा, ओबीसी, अनुसूचित जाति, महिला, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और किसान वर्ग तक अपनी पहुंच मजबूत करने की दिखाई दे रही है।

संगठन के बाद अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड

भाजपा के संगठनात्मक बदलाव के बाद अब सबसे बड़ा सवाल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर है। पार्टी के भीतर संभावित उम्मीदवारों पर शुरूआती मंथन शुरू होने की चर्चा है। मौजूदा विधायकों के कामकाज और क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का आकलन किए जाने की बात सामने आ रही है।

विधायकों की सक्रियता, क्षेत्र में किए गए काम और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता को लेकर सर्वे भी कराया जा सकता है। ऐसे में केवल मौजूदा विधायक होना टिकट की गारंटी नहीं माना जा रहा।

कमजोर प्रदर्शन वाले विधायकों पर गिरेगी गाज?

भाजपा की संभावित रणनीति के मुताबिक, जिन विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी है या जिनका प्रदर्शन अपेक्षित नहीं माना जाएगा, उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है।

पार्टी में युवाओं को अधिक संख्या में टिकट देने की चर्चा है। महिलाओं को भी चुनावी मैदान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में कई मौजूदा विधायकों के टिकट पर असमंजस की स्थिति बन सकती है।

सांसदों और परिवारवाद का मुद्दा भी अहम

भाजपा के भीतर कुछ सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताने की चर्चा भी है। वहीं, कुछ सांसद अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट की मांग कर सकते हैं।

ऐसी स्थिति में भाजपा के सामने परिवारवाद के खिलाफ अपनी राजनीतिक लाइन और नेताओं की व्यक्तिगत दावेदारी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी।

एनडीए में सीट बंटवारे का गणित

विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के सामने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का मुद्दा भी महत्वपूर्ण होगा। सहयोगी दल अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर अधिक सीटों की मांग कर सकते हैं।

पिछले चुनाव के बाद एनडीए में शामिल हुए सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ सीटों को लेकर बातचीत भी अहम मानी जा रही है। राजभर की पार्टी पहले ही अधिक सीटों पर अपनी दावेदारी के संकेत देती रही है।

ऐसे में भाजपा को सहयोगी दलों को पर्याप्त राजनीतिक हिस्सेदारी देने के साथ-साथ अपने संगठनात्मक प्रभाव और सीटों के समीकरण में संतुलन बनाए रखना होगा।

योगी आदित्यनाथ ही होंगे भाजपा का चेहरा

2027 के चुनाव को लेकर भाजपा ने नेतृत्व के सवाल पर अपना रुख स्पष्ट रखा है। पार्टी की रणनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही प्रमुख चेहरे के तौर पर आगे रखने की तैयारी

पीडीए के मुकाबले भाजपा का सामाजिक समीकरण

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। इसके जवाब में भाजपा भी ओबीसी, दलित, महिला, युवा और किसान मोर्चों को सक्रिय करने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। पार्टी की कोशिश अलग-अलग सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही इन सामाजिक समीकरणों को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच राजनीतिक मुकाबला और तेज होने की संभावना है।

दिखाई दे रही है।

योगी के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में 2027 का चुनाव योगी सरकार के कामकाज और उनके नेतृत्व पर जनता की मुहर के तौर पर भी देखा जाएगा।

नवरात्रि से बढ़ेगा केंद्रीय नेतृत्व का दखल

भाजपा की चुनावी रणनीति केवल संगठन और टिकट तक सीमित रहने वाली नहीं है। पार्टी की ओर से शारदीय नवरात्रि के बाद उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों के दौरों को बढ़ाने की तैयारी की चर्चा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी राज्य में अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना बताई जा रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में यूपी भाजपा का अभियान संगठन, राज्य सरकार और केंद्रीय नेतृत्व–तीनों स्तरों पर तेज होता दिखाई दे सकता है।

मिशन 2027 की उलटी गिनती शुरू

भाजपा की नई संगठनात्मक नियुक्तियां, विधायकों का संभावित रिपोर्ट कार्ड, टिकट के लिए सर्वे, नए चेहरों पर दांव, महिलाओं और युवाओं को मौका, एनडीए में सीट बंटवारे का गणित और मोदी-योगी की जोड़ी को केंद्र में रखकर चुनावी अभियान–इन सभी संकेतों से भाजपा की आगामी रणनीति की तस्वीर सामने आती है।

अब सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि भाजपा अपने संगठनात्मक ढांचे और सामाजिक समीकरणों को कितनी प्रभावी तरीके से वोट में बदल पाती है। साथ ही यह भी देखना होगा कि मौजूदा विधायकों में कितनों को दोबारा टिकट मिलता है और एनडीए के सहयोगी दल सीट बंटवारे को लेकर किस फामूर्ले पर सहमत होते हैं। फिलहाल, योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे और भाजपा की नई संगठनात्मक नियुक्तियों के साथ उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 की तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। आने वाले महीनों में टिकट बंटवारे से लेकर सामाजिक समीकरणों तक कई बड़े राजनीतिक फैसले यूपी की चुनावी दिशा तय कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री योगी के आवास पर भारत-जापान की युवा पीढ़ी का मिलन

'ए डायलॉग विद द फ्यूचर' में गूंजा दोस्ती और भविष्य का संदेश

अनिल वशिष्ठ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसमें कूटनीति की औपचारिकता की जगह बच्चों की मुस्कान थी, भाषाओं की दूरी की जगह संवाद था और दो देशों की संस्कृति के बीच दोस्ती का एक सहज सेतु बनता दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश-जापान निवेश बैठक के क्रम में आयोजित विशेष कार्यक्रम 'ए डायलॉग विद द फ्यूचर' में जापान के यामानाशी प्रान्त से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी प्रान्त के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में हुआ यह संवाद आने वाले भारत-जापान संबंधों की उस तस्वीर को सामने ला रहा था, जिसकी नींव आज की युवा पीढ़ी के मन में रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने जापान के यामानाशी से आए विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों तथा लखनऊ के युवा साथियों का आत्मीय स्वागत करते हुए जापानी अभिवादन 'ओहायो गोजाइमासु' से अपने संबोधन की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और 25 करोड़ से अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र है और इसे 'हार्टलैंड ऑफ इंडिया' के रूप में भी देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस अवध क्षेत्र में आज यह संवाद हो रहा है, उसी क्षेत्र में अयोध्या स्थित है, जो मयार्दा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि है। जापानी विद्यार्थियों ने आगरा में ताजमहल देखा, मथुरा, जो भगवान्‌ श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, पास में ही है और अब वाराणसी तथा सारनाथ जाने का अवसर उन्हें मिलेगा। सारनाथ वह पावन स्थल है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। वाराणसी दुनिया की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। इस तरह

जापान से आए इन विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश की यात्रा भारत की आध्यात्मिकता, संस्कृति और सभ्यतागत विरासत को करीब से जानने का अवसर भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं है। यह दो संस्कृतियों, दो परंपराओं और दो देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे समय में दोनों देशों के ये विद्यार्थी भविष्य के राजदूत के रूप में इस संबंध को नई ऊंचाई देने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक ओर भारत की सबसे बड़ी युवा कार्यशक्ति वाले उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और दूसरी ओर तकनीक, परंपरा और प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाने वाले जापान के बच्चे। एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, लेकिन दोनों के बीच सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान से आए विद्यार्थियों के लिए भारत की विविधता में एकता, वसुधैव कुटुम्बकम्, भारतीय भाषाओं, दर्शन, पर्व और त्योहारों तथा उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझने का यह अवसर है। उन्होंने कहा कि जापान की नई पीढ़ी भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक साझा सभ्यतागत मित्र के रूप में जाने, यह इस संवाद की बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं भारतीय विद्यार्थियों के लिए जापान की कार्य संस्कृति, जीवन दर्शन, अनुशासन, 'इकीगाई', टीमवर्क, पारस्परिक सम्मान, स्वच्छता, समयबद्धता, पारंपरिक कलाओं और उत्सवों को समझने का अवसर है। उन्होंने कहा कि आदान-प्रदान कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि दोनों देश एक-दूसरे से सीखें और अपनी श्रेष्ठ बातों को साझा करें।

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने जापान के सामाजिक सामंजस्य के दर्शन और भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की वैचारिकी के बीच की सुंदर समानता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति मानती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। 'अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम।' उन्होंने कहा कि यह अपना है और यह पराया है, ऐसी सोच संकुचित मन वाले लोगों की होती है, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए पूरी दुनिया ही एक परिवार है। इसी भावना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के संकल्प में भी देखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान की स्ट्रेंथ सेल्फ डिसिप्लिन, प्रिसिजन, क्वालिटी, टीम वर्क और इनोवेशन में है, जबकि भारत की शक्ति युवा शक्ति, प्रतिभा, विविधता, सृजनात्मकता और सबको साथ लेकर चलने की भावना में है। जब जापान की शक्ति और भारत की शक्ति साथ आएंगी, तो इसका लाभ केवल दोनों देशों के बच्चों को नहीं मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आज वे विद्यार्थी हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में इन्हीं में से वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, कलाकार, खेल चैंपियन, नीतिनिमार्ता और वैश्विक नेतृत्वकर्ता निकलेंगे।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे एक-दूसरे की भाषा सीखने के साथ एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का भी प्रयास करें। एक-दूसरे की संस्कृति, मूल्यों और जीवन दृष्टि का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि सबसे मजबूत रिश्ते कक्षाओं, परिसरों, प्रयोगशालाओं और युवा मस्तिष्कों के बीच बनते हैं। आज के यही बच्चे कल भारत-जापान साझेदारी के सबसे प्रभावशाली राजदूत होंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन का समापन जापानी भाषा में 'अरिगातो गोजाइमासु' कहकर किया।

यामानाशी प्रान्त के गवर्नर कोटारो नागासाकी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने दोनों देशों के विद्यार्थियों को संवाद का यह अवसर दिया। उन्होंने लखनऊ के विद्यार्थियों का भी विशेष धन्यवाद किया, जिन्होंने जापानी बच्चों का आत्मीय स्वागत किया। गवर्नर ने कहा कि दोनों देशों को और बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि हमारे बीच क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं। उन्होंने भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और यामानाशी की उस सोच का उल्लेख किया, जिसमें

एक-दूसरे के लोगों को समृद्ध बनाने के साथ अपनी समृद्धि को भी सुनिश्चित करने की भावना है।

गवर्नर कोटारो नागासाकी ने कहा कि यह मुलाकात केवल एक दिन का कार्यक्रम बनकर नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने जापानी और भारतीय मित्रों के साथ इस दोस्ती को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश साथ मिलकर समृद्ध हों और युवा पीढ़ी इस रिश्ते को और मजबूत बनाए, यही इस संवाद की सबसे बड़ी अपेक्षा है।

मुख्यमंत्री और जापानी गवर्नर के संबोधन के बाद संवाद और भी आत्मीय हो गया। जापानी विद्यार्थियों ने मिलकर जापानी भाषा में गीत प्रस्तुत किया। उनकी सामूहिक प्रस्तुति के दौरान मुख्यमंत्री आवास का वातावरण तालियों से गूंज उठा। इसके जवाब में भारत की ओर से ईशान ने भगवान श्रीराम को समर्पित 'कौशल्या दशरथ के नंदन' गीत प्रस्तुत किया। जापानी भाषा का मधुर गीत और रामभक्ति से सराबोर भारतीय गीत, दो अलग भाषाओं में प्रस्तुत इन दोनों गीतों ने एक ही भाव को सामने रखा, संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन संगीत और भावनाएं दिलों को जोड़ती हैं।

लखनऊ की छात्रा अक्षरा पांडेय ने जापानी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी यहां आए, यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि जापानी विद्यार्थियों को ताजमहल पसंद आया, यह उनके लिए भी सुखद है। उन्होंने अपने बचपन की याद साझा करते हुए कहा कि भारत के बच्चे डोरेमोन देखते हुए बड़े हुए हैं। भारत की संस्कृति में अतिथि को भगवान का स्वरूप माना जाता है, इसलिए जापान से आए सभी विद्यार्थी यहां केवल अतिथि नहीं, अपने हैं और उनका पूरा सम्मान है। उन्होंने जापानी भाषा में 'अरिगातो' कहकर उनका स्वागत किया।

जापानी विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव खुलकर साझा किए। जापानी छात्र कजामा ने कहा, 'भारत आना मेरे लिए बहुत खास अनुभव है, क्योंकि मैं पहली बार अपने देश से बाहर निकला हूं। यहां आकर जिस तरह लोगों ने हमसे मित्रवत व्यवहार किया, वह मेरे दिल को छू गया। भारत की सड़कों पर इतनी सारी मोटरसाइकिल और गाड़ियां देखना मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। टोक्यो में ऐसा अनुभव कम मिलता है। मुझे ताजमहल देखने का अवसर मिला। उसके सुंदर संगमरमर और भव्यता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। हम सभी हाईस्कूल के विद्यार्थी हैं और मैं चाहता हूं कि हम भारत और जापान के बीच मैत्री और समझ का सेतु बनें। आज यहां जो अनुभव मिला है, उसे मैं हमेशा याद रखूंगा।' जापानी छात्रा मियागी मोतो ने कहा, 'इतने लोगों के सामने अपने विचार साझा करने का अवसर मेरे लिए बहुत विशेष है। मैं पहले भी कई देशों के विद्यार्थियों के साथ ऐसे संवाद कार्यक्रमों का हिस्सा रही हूं, लेकिन भारत का अनुभव अपने आप में अलग है। मैं यामानाशी में रहती हूं और मेरा मानना है कि अलग-अलग संस्कृतियों को समझना और एक-दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। भारत आकर ताजमहल देखना मेरे लिए अद्भुत अनुभव रहा। मैंने पहली बार बिंदी लगाई और मुझे यह बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ 13 अन्य विद्यार्थी भी आए हैं और हम सभी इस यात्रा से मिली यादों और अनुभवों को अपने भविष्य का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मैं भारत और जापान की मित्रता को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए बहुत उत्सुक हूं।'

इसी क्रम में एक अन्य जापानी छात्रा ने कहा कि हम शांति और मैत्री की प्रार्थना करते हैं। जापानी विद्यार्थियों ने अपनी भावनाओं को ओरिगेमी की कला में भी पिरोया था। उन्होंने कागज से बनाए गए सुंदर ओरिगेमी के माध्यम से शांति और मित्रता का संदेश मुख्यमंत्री को भेंट किया। बच्चों के हाथों से बना यह छोटा सा उपहार अपने भीतर एक बड़ी भावना समेटे था, दो देशों की नई पीढ़ियों के बीच शांति, मित्रता और साथ आगे बढ़ने की कामना।

संवाद के आत्मीय माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने जापानी विद्यार्थियों और लखनऊ के बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर लेने को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखाई दिया। बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। यह सहज क्षण कार्यक्रम की औपचारिकता से अलग एक ऐसी याद बन गया, जिसे भारतीय और जापानी विद्यार्थी लंबे समय तक अपने साथ संजोकर रखेंगे।

मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को हुआ यह कार्यक्रम अंततः निवेश और आर्थिक साझेदारी से कहीं आगे निकलकर मानवीय रिश्तों का उत्सव बन गया। यहां 13 जापानी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों से मिले, अपनी भाषा में गीत सुनाया, ओरिगेमी के माध्यम से शांति और मित्रता का संदेश दिया और भारत के अनुभव अपने साथ लेकर लौटने की तैयारी की। वहीं भारतीय विद्यार्थियों ने जापानी संस्कृति को करीब से जाना और अपनी संस्कृति की झलक उन्हें दिखाई। एक तरफ यामानाशी के बच्चे थे, दूसरी तरफ लखनऊ के बच्चे। भाषाएं अलग थीं, संस्कृतियां अलग थीं, लेकिन भविष्य का सपना एक था। यही 'ए डायलॉग विद द फ्यूचर' की सबसे बड़ी तस्वीर रही, आज की दोस्ती से कल की मजबूत भारत-जापान साझेदारी की नींव।

यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026

नौ वर्षों में यूपी में 360 डिग्री बदलाव ने प्रदेश को बनाया निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन: मुख्यमंत्री

अरुण शर्मा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट के दौरान प्रमुख कंपनियों के सीईओज व बिजनेस लीडर्स के साथ आयोजित राउंड टेबल मीटिंग में निवेशकों का प्रदेश में निवेश के प्रति उत्साह दिखाने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में 360 डिग्री का व्यापक परिवर्तन हुआ है। इसी बदलाव के कारण आज उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख और ड्रीम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभरकर सामने आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले उद्यमियों और कंपनियों को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने निवेशकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे उत्तर प्रदेश आएं और यहां अपनी औद्योगिक एवं कारोबारी गतिविधियों का विस्तार करें। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि निवेशकों को किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

निवेशकों के सुझावों पर गंभीरता से होगा विचार

सीएम योगी ने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट को लेकर जिस तरह की उत्सुकता प्रमुख उद्योगपतियों और सीईओज ने दिखाई है, उसके लिए वह सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। निवेशकों की ओर से दिए गए सुझावों को प्रदेश सरकार की टीम ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि निवेशकों के सुझावों और अपेक्षाओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जो भी व्यावहारिक समस्याएं सामने आएंगी, उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सरकार और उसकी पूरी टीम निवेश अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

युवा मैनपावर और स्किलिंग बनेगी ताकत

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास बड़ी संख्या में युवा मैनपावर है। सरकार युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप स्किलिंग और अपस्किलिंग के अवसर उपलब्ध करा रही है। इससे निवेशकों को प्रशिक्षित और सक्षम मानव संसाधन उपलब्ध होगा। प्रदेश में बदलते औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, स्किल्ड मैनपावर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को मिलेगा।

भारत की आर्थिक विकास यात्रा के चार स्तंभों से यूपी में निवेश की अपार संभावनाएंः अश्विनी वैष्णव

जापान और उत्तर प्रदेश के बीच निवेश एवं औद्योगिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम 'यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026' में केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की आर्थिक विकास यात्रा और भविष्य की निवेश संभावनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के संबंध लंबे समय से विश्वास पर आधारित रहे हैं और उत्तर प्रदेश तथा जापान के बीच बढ़ती साझेदारी इस विश्वास को और मजबूत करेगी।

केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जापान और उत्तर प्रदेश के बीच इस महत्वपूर्ण पहल के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर तथा उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का भी स्वागत किया और कहा कि जापान के उद्योग जगत के लिए उत्तर प्रदेश में तेजी से अवसर खुल रहे हैं।

भारत की आर्थिक सोच को चार स्तंभों में समझाया

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि को चार प्रमुख स्तंभों के आधार पर समझा जा सकता है। इनमें सोशल, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, समावेशी विकास, मैन्युफैक्चरिंग एवं इनोवेशन और कानूनों तथा नियमों का सरलीकरण प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि भारत पिछले कुछ वर्षों से लगभग 6 से 8 प्रतिशत की सतत आर्थिक वृद्धि के दौर में है। इसके साथ महंगाई को नियंत्रण में रखने और देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाए रखने पर भी लगातार ध्यान दिया गया है। इससे भारत को आने वाले वर्षों में लंबे समय तक टिकाऊ विकास की मजबूत क्षमता मिली है।

जापान के निवेशकों को दिया उत्तर प्रदेश में निवेश का संदेश

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में आने वाले वर्षों में 6 से 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का लंबा दौर देखने को मिल सकता है। इस विकास यात्रा में रेलवे, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कृषि समेत लगभग हर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने जापान के उद्योग जगत से भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज तेजी से बदल रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए मजबूत आधार तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि जापान के निवेशकों के लिए संदेश स्पष्ट है- भारत में निवेश करें, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। सरकार निवेशकों की सहायता और सुविधा के लिए पूरी तरह तैयार है। निवेशकों की सफलता ही भारत और उत्तर प्रदेश की सफलता है। उन्होंने कहा कि भारत-जापान की मजबूत साझेदारी आने वाले वर्षों में दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

निवेशकों के लिए हर स्तर पर सपोर्ट

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में होने वाला निवेश निवेशकों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। प्रदेश सरकार अपनी नीतियों के दायरे में निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। सरकार का प्रयास है कि निवेश की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो तथा उद्यमियों को अपने कारोबार के विस्तार पर ध्यान देने के लिए बेहतर वातावरण मिले। सरकार की पूरी टीम निवेशकों के साथ खड़ी है और किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसके समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

'जो कहते हैं, उसे जमीन पर उतारते हैं'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल घोषणाएं करने में विश्वास नहीं करती, बल्कि जो कहती है, उसे धरातल पर उतारती है। पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में आए बदलाव को निवेशक स्वयं देख सकते हैं। कानून-व्यवस्था, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक वातावरण और निवेश के लिए तैयार नीतियों से आए बदलाव ने उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर पेश की है। सरकार की कार्यप्रणाली में आया यह बदलाव निवेशकों को भी दिखाई देगा।

इन्वेस्टमेंट मीट को बताया महत्वपूर्ण अवसर

मुख्यमंत्री ने इस इन्वेस्टमेंट मीट को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे संवाद के माध्यम से सरकार को उद्योग जगत की अपेक्षाओं और जरूरतों को समझने का अवसर मिलता है, वहीं निवेशकों को प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं और सुविधाओं की जानकारी मिलती है।

सीएम योगी ने विश्वास जताया कि प्रमुख उद्योग समूहों की उत्तर प्रदेश में बढ़ती रुचि से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को और गति मिलेगी। उन्होंने निवेशकों से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने और प्रदेश में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान भी किया।

यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026

जापानी तकनीक का लाभ छोटे किसानों तक पहुंचाएं, कृषि लागत घटाकर उत्पादकता बढ़ाएं: शिवराज सिंह चौहान

एन के शर्मा

उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश, तकनीक और औद्योगिक सहयोग को नई गति देने के उद्देश्य से आयोजित यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में जापानी तकनीक और विशेषज्ञता का लाभ भारतीय किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश को जापानी कंपनियों के निवेश के लिए मजबूत डेस्टिनेशन बताया।

उन्होंने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी केवल निवेश तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका लाभ किसानों, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पहुंचना चाहिए। भारत में विशाल बाजार, बड़ी युवा आबादी और कृषि क्षेत्र की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसे में जापान के साथ तकनीकी और औद्योगिक सहयोग से कृषि में नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। उन्होंने जापानी उद्योग और संस्थानों से ऐसी तकनीक और मशीनरी विकसित करने का आग्रह किया, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी उपयोगी और आसानी से उपलब्ध हो।

यूपी का महत्वपूर्ण पार्टनर है जापान

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट, कुशल मानव संसाधन, बेहतर कनेक्टिविटी, तेजी से विकसित होते इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश-अनुकूल नीतियों के कारण वैश्विक निवेश के लिए मजबूत डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। जापान उत्तर प्रदेश का विशेष और महत्वपूर्ण पार्टनर है तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया जापान यात्रा ने दोनों पक्षों के संबंधों को और मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश में शक्ति, परंपरा, प्रतिभा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, इनोवेशन और बड़े बाजार की क्षमता मौजूद है। उन्होंने जापानी उद्योग जगत का आह्वान करते हुए कहा कि जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और उत्तर प्रदेश के टैलेंट एवं बाजार की संभावनाओं को साथ लाकर रोजगार, इनोवेशन और सस्टेनेबल ग्रोथ के असीमित नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

किसानों की उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत

कृषि मंत्री ने कहा कि आज जरूरत ऐसी तकनीक की है, जिससे किसानों की उत्पादकता बढ़े, पानी की खपत और उत्पादन लागत कम हो तथा किसानों की आय में वृद्धि हो। कृषि क्षेत्र में

होने वाली रिसर्च का सीधा लाभ खेत तक पहुंचना चाहिए। रिसर्च केवल पेपर तक सीमित न रहे, बल्कि उसे ऐसे उत्पाद और तकनीक में बदला जाए, जिसे किसान आसानी से अपना सकें।

ग्रामीण युवाओं को भी विकास यात्रा से जोड़ने पर जोर

केंद्रीय मंत्री ने कृषि तकनीक के साथ गांव के युवाओं को जोड़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई कृषि मशीनरी और तकनीक के संचालन, रखरखाव तथा उससे जुड़े व्यवसायों में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इससे गांव का युवा विकास यात्रा का केवल दर्शक नहीं, बल्कि उसका सक्रिय भागीदार बनेगा। उन्होंने जापान से कृषि तकनीक के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल सेंटर बनाने में सहयोग करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के बीच बेहतर तालमेल से किसानों के लिए उपयोगी तकनीक विकसित की जा सकती है।

भारत-जापान संबंध केवल निवेश तक सीमित नहीं

शिवराज सिंह चौहान ने भारत और जापान के संबंधों को दो देशों के साथ-साथ दो संस्कृतियों के बीच मजबूत साझेदारी बताया। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति तथा जापान की तकनीकी दक्षता और औद्योगिक क्षमता मिलकर विकास की नई राह तैयार कर सकती है। जापान के साथ भारत की साझेदारी को केवल निवेश के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। तकनीक, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग इसका महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया जा रहा है। इसमें 200 से अधिक जापानी उद्योगपति, सीईओ, कारोबारी प्रतिनिधि और नीति-निमार्ता हिस्सा ले रहे हैं। यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट-2026 में जापानी कंपनियों के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

भारत-जापान के रिश्तों में नई मजबूती, यूपी के साथ बढ़ रही रणनीतिक साझेदारी: सुरेश खन्ना

उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मजबूत कानून-व्यवस्था, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश अनुकूल नीतियों ने उत्तर प्रदेश को सबसे संभावनाशील निवेश स्थलों में शामिल कर दिया है। जापान अब प्रदेश की विकास यात्रा में केवल निवेशक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में आगे बढ़ रहा है।

नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित उत्तर प्रदेश-जापान निवेश सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए सुरेश खन्ना ने कहा कि भारत और जापान के संबंध साझा मूल्यों, समान दृष्टिकोण और परस्पर प्राथमिकताओं के आधार पर लगातार मजबूत हो रहे हैं। जापान से आए बड़े प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश के प्रति जापानी उद्योग जगत का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटारो नागासाकी सहित जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

सुरेश खन्ना ने कहा कि सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी, विशाल उपभोक्ता बाजार, कुशल मानव संसाधन, नीति आधारित सुशासन और तेजी से विकसित हो रहा आधारभूत ढांचा यूपी की बड़ी ताकत हैं। 'निवेश मित्र' जैसी व्यवस्थाओं ने कारोबार की राह आसान की है और निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया को गति दी है।

उन्होंने कहा कि गत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा से दोनों पक्षों के बीच औद्योगिक और संस्थागत संवाद को नई गति मिली है।

अब ग्रीन हाइड्रोजन, ऑटोमोबाइल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर प्रदेश जापान को सिर्फ निवेशक के रूप में नहीं देखता, बल्कि सतत और दीर्घकालिक विकास के विश्वसनीय साझेदार के रूप में उसका स्वागत करता है।

उन्होंने विश्वास जताया कि यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 दोनों पक्षों के आर्थिक, औद्योगिक और संस्थागत संबंधों को नई ऊंचाई देगा।

उत्तराखंड सरकार: विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

(पुष्कर सिंह धामी सरकार के पाँच वर्ष और आगे की राह)

इंद्रेश शर्मा

उत्तराखंड भारत का वह पहाड़ी राज्य है जो हिमालय की गोद में बसा है। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध यह राज्य न केवल प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में शासन-प्रशासन की स्थिरता और विकास की नई दिशा का भी उदाहरण बन गया है। जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के इतिहास में पहली बार पाँच वर्ष लगातार मुख्यमंत्री पद पर रहने का कीर्तिमान स्थापित किया। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड में पहले नेतृत्व परिवर्तन की आवृत्ति अधिक रही है। धामी सरकार ने 'विकसित उत्तराखंड-2035' का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के केंद्र में बुनियादी ढाँचा, रोजगार, पर्यटन, उद्योग, युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा शामिल है। केंद्र सरकार के 'डबल इंजन' शासन के साथ मिलकर राज्य ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इनमें समान नागरिक संहिता (UCC) का लागू होना सबसे प्रमुख है। उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना जिसने वउउ को लागू किया। इसके अलावा धर्मांतरण विरोधी कानून, नकल विरोधी कानून, सख्त भू-कानून और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता जैसे कदम भी राज्य की नीतिगत पहचान बन गए हैं।

पाँच वर्षों की स्थिरता और प्रमुख उपलब्धियाँ

पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया। जुलाई 2026 में उन्होंने पाँच वर्ष पूरे किए। इस दौरान सरकार ने दावा किया कि पिछले पाँच वर्षों में 34,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी नौकरियाँ मिलीं। बेरोजगारी दर में कमी आई और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दिए गए।

आर्थिक मोर्चे पर राज्य की प्रगति उल्लेखनीय रही। जीएसडीपी में वृद्धि हुई और निवेश आकर्षित करने के लिए 30 से अधिक नई नीतियाँ लागू की गईं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बड़े एमओयू साइन हुए और कई परियोजनाएँ जमीन पर उतरीं। पिछले पाँच वर्षों में 20,000 से अधिक उद्योग स्थापित होने का दावा किया गया। स्टार्टअप्स की संख्या भी लगभग 700 से बढ़कर 1,750 के आसपास पहुँची।

पर्यटन क्षेत्र में भी रिकॉर्ड तोड़े गए। 2025 में 6 करोड़ से अधिक पर्यटक राज्य पहुँचे। चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। होमस्टे योजना और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया। 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की पहल शुरू हुई। सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट मिशन और सगंध कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 'लखपति दीदी' अभियान उल्लेखनीय रहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 70,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया। इनमें से 3 लाख से अधिक महिलाएँ लखपति दीदी बनीं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत 13,000 से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया गया, जिनमें 8,000 से अधिक महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह की सदस्य शामिल हैं।

अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री ने 'चौपाल-2026' का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने देहरादून के आईटी पार्क स्थित 13 गाँव में राज्य स्तरीय विपणन केंद्र खोलने की घोषणा की, ताकि सभी जिलों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद आसानी से बिक सकें। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को

मजबूत करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

हालिया महत्वपूर्ण घोषणाएँ और नीतिगत निर्णय

स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने सात प्रमुख घोषणाएँ कीं। इनमें चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करना, प्रदेश का पहला युवा आयोग बनाना, 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करना, सीमावर्ती गाँवों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को विशेष प्रोत्साहन देना, प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये करना, वर्ग-3 और वर्ग-4 भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ाना तथा साहसी बच्चों के लिए बाल वीरता पुरस्कार शामिल हैं। अगस्त 2026 की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाया गया और सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी लाभ दिया जाने लगा। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 लागू की गई, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान, डिजिटल भुगतान और समान काम के लिए महिला-पुरुष को समान वेतन सुनिश्चित किया गया। हाईकोर्ट परिसर के लिए हल्द्वानी क्षेत्र में 40 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। खेल विश्वविद्यालय में 122 पद सृजित किए गए। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ, जिससे कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में अच्छी प्रगति हुई। अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष पात्र ग्रामीण परिवारों को निर्धारित समयसीमा में नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएँ। राज्य में 16,555 योजनाओं में से 15,540 पूरी हो चुकी थीं (लगभग 92 प्रतिशत) और ग्रामीण परिवारों में नल जल कवरेज 14.20 लाख से अधिक हो चुका था। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को 'पूर्ण साक्षर' घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप काम आगे बढ़ाया जा रहा है।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

कोई भी सरकार चुनौतियों से मुक्त नहीं होती। उत्तराखंड में पलायन अभी भी बड़ी समस्या है। युवा रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों या अन्य राज्यों की ओर जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और स्थानीय रोजगार सृजन अभी भी प्राथमिकता है। कुछ भर्ती परीक्षाओं में लीक के आरोप लगे, जिन पर विपक्ष ने आलोचना की। अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामले समय-समय पर सरकार पर दबाव बनाते रहे। भारी बारिश और आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई और पुनर्वास भी निरंतर चुनौती है। विपक्षी दल सरकार की कुछ नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। फिर भी सरकार का दावा है कि पारदर्शी भर्ती, सख्त कानून और विकास कार्यों से राज्य आगे बढ़ रहा है।

बुनियादी ढाँचा, सीमावर्ती विकास और आपदा प्रबंधन

राज्य में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएँ चल रही हैं। इनमें सड़क, रेल, बिजली, पर्यटन और पेयजल संबंधी परियोजनाएँ शामिल हैं। रुद्रप्रयाग ब्रिज-टनल परियोजना के पूरा होने से बद्रीनाथ-केदारनाथ मार्ग पर यातायात आसान होने की उम्मीद है। सीमावर्ती गाँवों के विकास के लिए मुख्यमंत्री सीमा क्षेत्र विकास योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर जोर दिया जा रहा है। हालाँकि मानसून के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और सड़क अवरोध जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं। अगस्त 2026 में कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया और दर्जनों सड़कें प्रभावित हुईं। चमोली में टीएचडीसी टनल हादसे में मजदूरों की जानें गईं। मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर राहत-बचाव कार्यों का जायजा लिया और मुआवजे की घोषणा की। आपदा प्रबंधन और रोड क्लीयरेंस पर प्रशासन लगातार काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वन विभाग के आँकड़ों के अनुसार पिछले चार वर्षों में जंगलों में पानी की उपलब्धता बढ़ी है। वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के प्रयास जारी हैं। कुछ सड़क परियोजनाओं में पेड़ कटान को लेकर विरोध भी हुआ, जिस पर सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई।

आगे की राह: 2035 का विजन

मुख्यमंत्री धामी ने बार-बार कहा है कि उनका लक्ष्य केवल कार्यकाल पूरा करना नहीं, बल्कि 2035 तक उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना है। इसके लिए उद्योग, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा और महिला सशक्तिकरण पर समान जोर दिया जा रहा है। युवा आयोग के गठन से युवाओं को नीति-निर्माण में भागीदारी मिलेगी। पर्वतीय जिलों में औद्योगिक पार्क स्थापित करने से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।

स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदियों और उद्यमशाला योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मॉडल राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन को और टिकाऊ बनाने, इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने से आर्थिक लाभ स्थानीय लोगों तक पहुँचेगा।

उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक विकास का संतुलन बनाना सरकार की प्राथमिकता है। वउउ, भू-कानून और अन्य सख्त कानूनों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था और भूमि सुरक्षा पर जोर दिया गया है।

पुष्कर सिंह धामी सरकार के पाँच वर्ष स्थिरता, साहसिक नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों का मिश्रण रहे हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनना, हजारों युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं को लखपति बनाने का अभियान, पर्यटन में रिकॉर्ड और निवेश आकर्षित करने के प्रयास उल्लेखनीय हैं। हालिया घोषणाएँ–युवा आयोग, औद्योगिक पार्क, विपणन केंद्र और मजदूरी संहिता–भविष्य की दिशा स्पष्ट करती हैं।

चुनौतियाँ अभी बाकी हैं-पलायन रोकना, आपदा प्रबंधन को और मजबूत करना, पहाड़ी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करना और पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास का संतुलन बनाए रखना। यदि सरकार इन चुनौतियों पर निरंतर ध्यान देती रही और केंद्र-राज्य समन्वय बना रहा, तो 'विकसित उत्तराखंड-2035' का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में राज्य मजबूती से आगे बढ़ सकता है।

देवभूमि उत्तराखंड न केवल पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आश्रय है, बल्कि अपने नागरिकों के लिए भी समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक बनने की ओर अग्रसर है। स्थिर शासन, साहसिक निर्णय और जन-कल्याण की भावना के साथ यह यात्रा जारी है।

तुलसीदासः भक्ति, लोकमंगल और जीवन-दर्शन के अमर व्याख्याता

मनोज शर्मा

भारत की संत-परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान केवल एक महान कवि अथवा रामभक्त के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-दर्शन के लोकनायक और सांस्कृतिक राष्ट्रनायक के रूप में है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को मनाई जाने वाली तुलसीदास जयंती हमें उस महापुरुष के स्मरण का अवसर देती है, जिसने रामकथा को राजमहलों और संस्कृत के विद्वत्-वर्ग से निकालकर जन-जन की भाषा, संवेदना और जीवन का हिस्सा बना दिया।

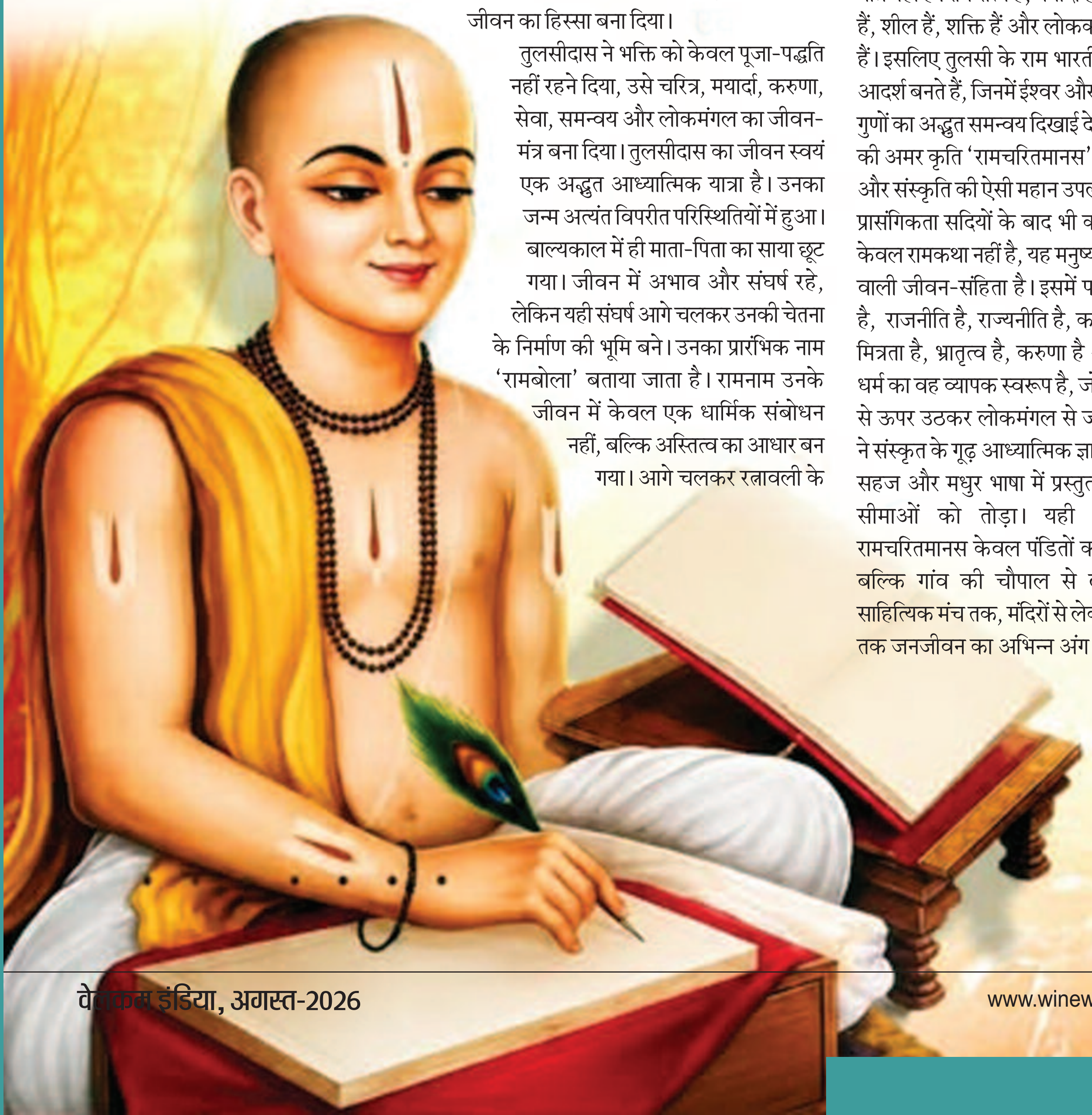

तुलसीदास ने भक्ति को केवल पूजा-पद्धति नहीं रहने दिया, उसे चरित्र, मर्यादा, करुणा, सेवा, समन्वय और लोकमंगल का जीवन-मंत्र बना दिया। तुलसीदास का जीवन स्वयं एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है। उनका जन्म अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में हुआ। बाल्यकाल में ही माता-पिता का साया छूट गया। जीवन में अभाव और संघर्ष रहे, लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर उनकी चेतना के निर्माण की भूमि बने। उनका प्रारंभिक नाम 'रामबोला' बताया जाता है। रामनाम उनके जीवन में केवल एक धार्मिक संबोधन नहीं, बल्कि अस्तित्व का आधार बन गया। आगे चलकर रत्नावली के जीवन-परिवर्तनकारी वचन ने उनके भीतर वैराग्य की ऐसी ज्योति प्रज्वलित की, जिसने सांसारिक आसक्ति को रामभक्ति की विराट धारा में परिवर्तित कर दिया।

तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने भक्ति और जीवन को अलग-अलग खानों में नहीं बांटा। उनके लिए राम मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति मात्र नहीं हैं। राम सत्य हैं, मर्यादा हैं, नीति हैं, करुणा हैं, शील हैं, शक्ति हैं और लोककल्याण की प्रेरणा हैं। इसलिए तुलसी के राम भारतीय मानस के ऐसे आदर्श बनते हैं, जिनमें ईश्वर और मनुष्य के श्रेष्ठतम गुणों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। तुलसीदास की अमर कृति 'रामचरितमानस' भारतीय साहित्य और संस्कृति की ऐसी महान उपलब्धि है, जिसकी प्रासंगिकता सदियों के बाद भी कम नहीं हुई। यह केवल रामकथा नहीं है, यह मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली जीवन-संहिता है। इसमें परिवार है, समाज है, राजनीति है, राज्यनीति है, कर्तव्य है, त्याग है, मित्रता है, भ्रातृत्व है, करुणा है और सबसे ऊपर धर्म का वह व्यापक स्वरूप है, जो व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठकर लोकमंगल से जोड़ता है। तुलसी ने संस्कृत के गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान को अवधी की सहज और मधुर भाषा में प्रस्तुत करके ज्ञान की सीमाओं को तोड़ा। यही कारण है कि रामचरितमानस केवल पंडितों का ग्रंथ नहीं बना, बल्कि गांव की चौपाल से लेकर नगरों के साहित्यिक मंच तक, मंदिरों से लेकर घरों के आंगन तक जनजीवन का अभिन्न अंग बन गया। तुलसी

ने जिस भाषा में लिखा, वह जनता की भाषा थी, जिस कथा को चुना, वह जनमानस की आस्था से जुड़ी थी और जिन मूल्यों को सामने रखा, वे सार्वकालिक थे। इसीलिए तुलसी का साहित्य कालजयी बना।

काशी में उनके ग्रंथ को लेकर मधुसूदन सरस्वती जैसे महान विद्वान ने तुलसी की काव्यप्रतिभा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि काशी रूपी आनंदवन में तुलसीदास चलते-फिरते तुलसी-वृक्ष हैं और उनकी काव्य-मंजरी पर रामरूपी भ्रमर मंडरा रहा है। यह टिप्पणी केवल प्रशंसा नहीं, बल्कि तुलसी की आध्यात्मिक और साहित्यिक ऊंचाई की स्वीकृति के रूप में देखी जाती है। तुलसीदास की भक्ति निष्क्रिय पलायन की भक्ति नहीं है। वह मनुष्य को कर्म से विमुख नहीं करती, बल्कि कर्तव्य के प्रति जागरूक करती है। उनके राम वन जाते हैं तो कर्तव्य के कारण। भरत राजसत्ता ठुकराते हैं तो भ्रातृप्रेम और त्याग के कारण। हनुमान सेवा करते हैं तो पूर्ण समर्पण के साथ। सीता संकट में भी धैर्य और आत्मबल का परिचय देती हैं। तुलसी के लिए भक्ति का अर्थ है- अहंकार का विसर्जन और अपने भीतर के श्रेष्ठतम मनुष्य का जागरण। उनका रामभक्त स्वयं को ईश्वर के सामने समर्पित करता है, लेकिन संसार से भागता नहीं। वह समाज, परिवार और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को अधिक गंभीरता से निभाता है। इसीलिए तुलसी की भक्ति में ज्ञान, कर्म और प्रेम का त्रिवेणी-संगम दिखाई देता है।

तुलसीदास को केवल धार्मिक कवि मानना उनके विराट व्यक्तित्व को सीमित करना होगा। उनके साहित्य में तत्कालीन समाज की विसंगतियों, विघटन और नैतिक संकटों की गहरी अनुभूति है। उन्होंने समाज को कोई राजनीतिक घोषणा-पत्र नहीं दिया, बल्कि चरित्र-निर्माण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का रास्ता दिखाया। उनके रामराज्य की कल्पना में शासन का उद्देश्य सत्ता नहीं, लोककल्याण है।

रामराज्य में व्यक्ति भयमुक्त, सम्मानपूर्ण और संतुलित जीवन जीता है। तुलसी के साहित्य का यह पक्ष आज भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक समाज में विकास के साथ-साथ नैतिकता, संवेदना और सामाजिक विश्वास का संकट भी दिखाई देता है। आज परिवार टूट रहे हैं, संबंधों में स्वार्थ बढ़ रहा है, सार्वजनिक जीवन में मयार्दा का क्षरण हो रहा है और व्यक्ति भौतिक

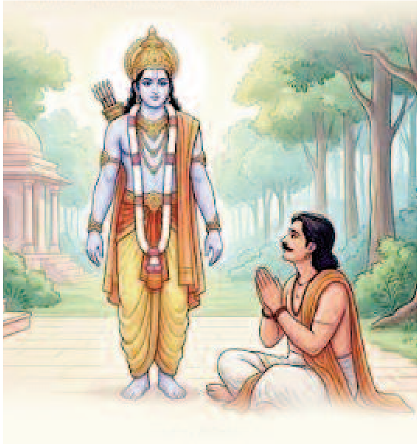

जीवन में अभाव और संघर्ष रहे, लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर उनकी चेतना के निर्माण की भूमि बने। उनका प्रारंभिक नाम 'रामबोला' बताया जाता है। रामनाम उनके जीवन में केवल एक धार्मिक संबोधन नहीं, बल्कि अस्तित्व का आधार बन गया।

उपलब्धियों के बावजूद भीतर से अशांत है। ऐसे समय में तुलसी का साहित्य हमें याद दिलाता है कि सभ्यता की वास्तविक शक्ति उसके चरित्र में होती है, केवल उसकी संपन्नता में नहीं। रामराज्य को केवल किसी प्राचीन शासन-व्यवस्था के रूप में देखना उचित नहीं होगा। यह एक नैतिक और मानवीय व्यवस्था का आदर्श है, जहां शासन लोकहितकारी हो, न्याय निष्पक्ष हो, समाज में परस्पर विश्वास हो और व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी समझे।

तुलसीदास का कृतित्व अत्यंत व्यापक है। 'रामचरितमानस', 'विनय-पत्रिका', 'कवितावली', 'गीतावली', 'दोहावली', 'कृष्णगीतावली', 'जानकीमंगल', 'पार्वतीमंगल', 'रामलला नहछू', 'वैराग्यसंदीपनी' और 'हनुमान बाहुक' आदि उनकी साहित्यिक प्रतिभा के विविध आयामों को सामने रखते हैं। 'विनय-पत्रिका' में भक्त का आत्मसमर्पण है तो 'कवितावली' में जीवन और समाज के अनुभवों की तीखी संवेदना भी है। 'हनुमान बाहुक' में व्यक्तिगत पीड़ा और आध्यात्मिक आश्रय का अद्भुत संगम दिखाई देता है। इस दृष्टि से तुलसी केवल रामकथा के कवि नहीं, बल्कि मनुष्य की बाहरी और भीतरी दोनों यात्राओं के कवि हैं। तुलसीदास का सबसे महत्वपूर्ण संदेश समन्वय है। उन्होंने ज्ञान और भक्ति, लोक और शास्त्र, आदर्श और यथार्थ, व्यक्ति और समाज तथा अध्यात्म और व्यवहार के बीच पुल बनाया। उनका साहित्य विभाजन नहीं, समरसता की ओर ले जाता है। उनकी दृष्टि में धर्म संकीर्ण पहचान नहीं, बल्कि जीवन को सत्य, करुणा, संयम और मयार्दा से जोड़ने वाली शक्ति है। यही कारण है कि रामचरितमानस का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, उसने भारतीय कला, संगीत, नाटक, लोकपरंपरा, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक स्मृति को गहराई से प्रभावित किया।

आज तकनीक ने संसार को छोटा कर दिया है, लेकिन मनुष्य का मन कई बार अकेला और अस्थिर होता जा रहा है। सूचना बहुत है, लेकिन विवेक का अभाव दिखाई देता है। संपत्ति बढ़ रही है, लेकिन संतोष घट रहा है। संपर्क बढ़ रहे हैं, लेकिन संबंध कमजोर हो रहे हैं। ऐसे समय में तुलसीदास का संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक है। रामचरितमानस हमें सिखाता है कि विकास के साथ मूल्य, शक्ति के साथ विनम्रता, ज्ञान के साथ विवेक और अधिकार के साथ कर्तव्य आवश्यक है। तुलसी का राम हमें भीतर के रावण से लड़ने की प्रेरणा देता है। बाहरी विजय से पहले अंतर्मन की विजय आवश्यक है। तुलसी की यही सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने राम को केवल अयोध्या का राजा नहीं रहने दिया, बल्कि भारतीय चेतना के भीतर का आदर्श मनुष्य बना दिया। तुलसीदास का जीवन हमें बताता है कि परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनातीं, बल्कि मनुष्य अपनी चेतना से परिस्थितियों को अर्थ देता है। एक संघर्षशील जीवन से उठकर तुलसी ने ऐसा साहित्य रचा, जिसने भारत की कई पीढ़ियों को संस्कार दिए।

तुलसीदास भारतीय संस्कृति की स्मृति मात्र नहीं, उसकी जीवंत चेतना हैं। उनकी भक्ति हमें भीतर की यात्रा कराती है, उनका साहित्य जीवन का विवेक देता है और उनका राम हमें यह विश्वास दिलाता है कि मनुष्य अपने आचरण से स्वयं को ऊंचा उठा सकता है। तुलसी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम रामचरितमानस को केवल पढ़ें नहीं, अपने जीवन में चरितार्थ करें। यही तुलसी का जीवन-दर्शन है, यही उनके कृतित्व की सार्थकता है और यही आज के अशांत, विभाजित और मूल्य-संकट से जूझते समाज के लिए उनकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता भी है।

भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर

सावन मास की शुरूआत होते ही हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, गंगा गंगोत्री से लेकर रामेश्वरम तक सम्पूर्ण भारत शिवमय हो उठता है। सावन मास में शिवभक्तों की विशाल पदयात्राएं जो कांवड़ यात्रा के नाम से जानी जाती है, भारतीय संस्कृति की जीवंतता का अनुपम दृश्य प्रस्तुत करती हैं। कंधों पर सुसज्जित कांवड़, मुख पर बोल बम का उद्घोष, हृदय में भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति। यही है कांवड़ यात्रा का वास्तविक स्वरूप।

कांवड़ यात्रा केवल एक सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि ये तपस्या, भक्ति और श्रद्धा की वह गाथा है जो शताब्दियों से चली आ रही है।

धर्मशास्त्रों के अनुसार जब कांवड़ से जुड़े दोनों पात्र जिन्हें ब्रह्मघट और विष्णुघट कहा जाता है, पवित्र जल से भर लिए जाते है, तो उन्हें एक बांस की डण्डी के सहारे सजा-धजा कर और पूजित कर, स्थापित कर दिया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार रूद्र अर्थात शिव बांस में समाहित हैं। कांवड़िया कांवड़ के माध्यम से साक्षात ब्रह्मा,

अरुण मिश्रा

विष्णु, शिव, तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त करते हैं। भारत में दो कांवड़ यात्राएं होती हैं, दिल्ली से उत्तराखंड-गंगोत्री, ऋषिकेश या हरिद्वार तक की कांवड़ यात्रा और बिहार और झारखंड में सुल्तानगंज से देवघर तक की कांवड़ यात्रा।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सैकड़ों-हजारों लोग, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, जिनमें महिलाएं और कभी-कभी बच्चे भी कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। कंधों पर लटका पवित्र जल भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें अक्सर भोला या भोले बाबा कहकर पुकारा जाता है। भोले का अर्थ भोलेनाथ, यानी भगवान शिव भी हो सकता है। इसलिए, तीर्थयात्री भोला और भोले हैं!

वर्तमान में, कांवड़ यात्रा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक पदयात्राओं में मानी जाती है। आधुनिक समय में इसकी भव्यता अत्यधिक बढ़ी है, किंतु इसकी आध्यात्मिक जड़ें वैदिक एवं पौराणिक परंपराओं में गहराई तक समाई हुई हैं। प्राचीन ग्रंथों में कांवड़ यात्रा का उल्लेख प्रायः किया जाता है। यह प्रश्न बार-बार पूछा जाता है कि कांवड़ यात्रा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उत्तर थोड़ा सूक्ष्म है।

कांवड़ शब्द अपने वर्तमान अर्थ में पुराणों में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता। किंतु पवित्र नदी से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करने की परंपरा का वर्णन अनेक पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है। वर्तमान कांवड़ यात्रा उसी प्राचीन शिवाभिषेक परंपरा का आधुनिक स्वरूप मानी जाती है। अर्थात कांवड़ यात्रा का भाव पुराण सम्मत है, जबकि कांवड़ शब्द अपेक्षाकृत उत्तरकालीन लोक प्रचलित नाम है। कंवार शब्द की व्युत्पत्ति, जिसका अर्थ कंधा है। कांवड़ में दूर-दूर से पवित्र नदियों, खासकर गंगा का जल भरकर लाते हैं।

इसे पैदल यात्रा करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस संकल्प यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होता है कांवड़ को अपने कंधे पर उठाकर ले जाना। यह कोई साधारण परंपरा नहीं है। इसके पीछे गहराई से जुड़ी हुई पौराणिक मान्यताएं छुपी हुई हैं। वाकई में कांवड़ यात्रा का जिक्र किसी पौराणिक ग्रंथ में सीधे तौर पर नहीं मिलता है। इसका भी स्पष्ट रूप से कोई जिक्र नहीं है कि किसने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी, लेकिन लोक व्यवहार में महाबली रावण, महाविष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम, अगस्त्य ऋषि, महर्षि मार्कंडेय, महारथी कर्ण और 61 नयनार संतों में से एक संत कनप्पा जैसे कई नाम शामिल हैं, जिन्होंने महादेव शिव को बड़ी सरल-सहज और आसान विधि से पूजन कर प्रसन्न किया था। रावण और भगवान परशुराम द्वारा तो शिवजी के लिए कांवड़ लाकर भी उनका जलाभिषेक करने का प्रसंग लोक कथाओं में मिलता है, हालांकि पुराणों में हर जगह इनके द्वारा की गई विधिवत पूजा का ही वर्णन मिलता है, जिसमें पंचोपचार पूजन से लेकर, षोडशोपचार पूजन तक का वर्णन मिलता है, फिर भी कांवड़ द्वारा जल लाकर शिवजी के अभिषेक का वर्णन नहीं मिलता है। हालांकि कांवड़ शब्द का जिक्र रामायण में मिलता है। जहां राजा दशरथ द्वारा गलती से श्रवण कुमार की हत्या हो जाती है। इस प्रसंग में जब श्रवण कुमार के चरित्र का वर्णन आता है तब कांवड़ का जिक्र होता है। जहां पता चलता है कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता-पिता को कांवड़ में बैठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाता है। कांवड़ असल में तराजू जैसी आकृति का एक नमूना होता है। श्रवण ने अपने माता-पिता को दोनों ओर बिठा लिया और कांवड़ कंधे पर रखकर चला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीर्थ क्षेत्र में दशानन रावण से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। यहां नोएडा के पास बिसरख गांव को रावण की जन्मस्थली बताया जाता है। मेरठ को मयराष्ट्र बताते हुए उसे रावण की ससुराल बताया जाता है। यहीं बागपत स्थित पुरा महादेव मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहां पर खुद रावण ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल लाकर शिवजी का जलाभिषेक किया था, जबकि रावण से भी सैकड़ों वर्ष पहले भगवान परशुराम ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी और 108 कलश से उनका अभिषेक किया था।

स्कंद पुराण में शिव उपासना के लिए रामोपाख्यान सर्ग में एक जिक्र आता है, जहां शिवगण नंदी और रावण की बातचीत होती है. इस स्थान पर नंदी कहते हैं कि जो प्राणी जलाशय से शिवालय तक पैदल ही गमन करता है, और फिर जल ले जाकर शिवालय को धोकर साफ करता है, वह बिना किसी विधान की पूजा के शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि स्कंद पुराण में कांवड़ यात्रा का जिक्र नहीं है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि 'जलाशय से जल लेकर शिवालय तक की यात्रा'. संभवतः आगे चलकर यही व्याख्या कांवड़ यात्रा के संदर्भ में ली गई होगी।

हालांकि कांवड़ यात्रा विशुद्ध ग्रामीण परंपरा है और इसकी शुरूआत इधर के आधुनिक काल में ही कभी हुई हो, इसकी अधिक संभावना हो सकती है। शिवजी की कावड़ यात्रा का जिक्र पुराणों में मिले न मिले, किसी रावण ने कांवड़ पहले चढ़ाई हो या नहीं, शिवभक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए तो बस इतनी सी बात है, वे शिव के हैं और शिव उनके हैं। वहीं कांवड़ के व्युत्पत्तिपरक जो अर्थ किए गए हैं, उनमें एक के अनुसार क अक्षर अग्नि को द्योतक है और आवर का अर्थ ठीक से वरण करना। प्रार्थना यह है कि अग्नि अर्थात स्रष्टा, पालक एवं संहारकर्ता परमात्मा हमारा मार्गदर्शक बने और वही हमारे जीवन का लक्ष्य हो तथा हम अपने राष्ट्र और समाज को अपनी शक्ति से सक्षम बनाएं। गंगाजल, पारद, पाषाण, धतूराफल आदि सबमें शिव सत्ता मानी गई है। अतः सब प्राणियों, जड़-जंगम पदार्थों में स्वयं भूतनाथ पशुपतिनाथ की सुगमता और सुलभता ही तो आपको देवाधिदेव महादेव सिद्ध करती है। कांवड़ शिव के उन सभी रूपों को नमन है। कंधे पर गंगा को धारण किए श्रद्धालु इसी आस्था और विश्वास को जीते हैं। यों भी कह सकते हैं कि कांवड़ यात्रा शिव के कल्याणकारी रूप और निष्ठा के नीर से उसके अभिषेक को तीव्र रूप में प्रतिध्वनित करती है। वास्तव में, कांवड़ यात्रा का यह धार्मिक उत्सव न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर भी है।

कांवड़िये इस यात्रा के माध्यम से न केवल अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, बल्कि यह यात्रा उन्हें एकजुटता और भाईचारे का भी अनुभव कराती है। इस दौरान भक्तों की भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जो भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाता है। सही मायनों में, कांवड़ यात्रा भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में निहित सिद्धांतों की पुनर्स्थापना है। कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये महादेव को शीतल जल अर्पित करने की परंपरा है, ये लोक-उत्सव है, समानता का सन्देश है क्योंकि चारों तरफ भगवा ही भगवा दिखता है जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है।

चुनौतियों की पाठशाला से ही मिलती है जिंदगी की असली सीख

मुहम्मद परवेज अख्तर
संतकबीरनगर

अगर किसी युद्ध में एक व्यक्ति के पास सारे अस्त्र-शस्त्र विद्यमान हों, लेकिन उसका शत्रु पूरी तरह निहत्था हो, निश्चित ही ऐसे युद्ध का परिणाम पहले व्यक्ति के पक्ष में होगा। मगर गहन विचार किया जाए, तो क्या ऐसी विजय जीते हुए व्यक्ति को कोई नई सीख, नया अनुभव या नया कौशल प्रदान करने में समर्थ होगी? इसका सीधा सा उत्तर है- नहीं। जीवन भी युद्ध का ही एक पर्याय है।

समय-समय पर हमारे सामने उपस्थित होने वाली परिस्थितियां और चुनौतियां युद्ध के शत्रु के बजाय हमारे लिए एक उत्कृष्ट पाठशाला की भूमिका अदा करती हैं। खुद को जानने के लिए जीवन में चुनौतियों की पाठशाला का होना नितांत आवश्यक है। चुनौतियां और कठिन परिस्थितियां हमें जीवन की सच्चाई के साथ-साथ हमारे भीतर छिपी हुई सामर्थ्य तथा अपार संभावनाओं से रूबरू कराती हैं। चुनौतियों में अपार शक्ति होती है। जिस प्रकार एक पाठशाला व्यक्ति को निरक्षर से साक्षर बना देती है, ठीक उसी तरह चुनौतियां भी हमारे व्यक्तित्व को रूपांतरित कर देती हैं।

यह पूरी तरह सच है कि चुनौतियां सबसे पहले व्यक्ति को विचलित करते हुए उसके आत्मविश्वास को क्षीण करने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनकी इस क्रिया का उत्तर कुशलतापूर्वक धैर्य की प्रतिक्रिया से दे दिया गया, तो फिर यही चुनौतियां हमारे व्यक्तित्व को अथाह आत्मविश्वास से भर देती हैं। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है। वास्तव में चुनौतियां मनुष्य को उसकी सीमाओं एवं अद्भुत शक्तियों से परिचित कराती हैं। शांत समुद्र में कोई भी नाविक कुशल नहीं बन सकता। कुशलता सदैव तूफानों से लड़कर ही आती है।

मनुष्य संघर्षों की भट्ठी में तपकर निखरता है। कठिनाइयां हमें धैर्य, संयम, साहस और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती हैं। यही कारण है कि जिन लोगों ने जीवन में संघर्ष और विषम परिस्थितियों का सामना किया होता है, वे अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील, परिपक्व और मजबूत दिखाई देते हैं। दरअसल, चुनौतियों से बचने की प्रवृत्ति ही सबसे बड़ी समस्या है। आज व्यक्ति आसान एवं वैकल्पिक मार्ग खोजने में लगा है। वह बिना परिश्रम के उत्कृष्ट परिणाम चाहता है। मगर प्रकृति का स्पष्ट सा नियम है- बिना संघर्ष के विकास संभव नहीं है। बीज अगर मिट्टी के अंधेरे और दबाव को सहन न करे, तो वह वृक्ष कदापि नहीं बन सकता। नदी चट्टानों से न टकराए तो उसका प्रवाह निर्मल नहीं हो सकता।

इसी प्रकार मनुष्य भी चुनौतियों से जूझे बिना परिपक्वता को नहीं प्राप्त कर सकता। चुनौतियों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे मनुष्य को आत्ममंथन का अवसर देती हैं। जब सब कुछ अनुकूल होता है, तब व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कठिन समय उसे स्वयं से परिचित कराता है। चुनौतियों की पाठशाला में प्रवेश लेकर ही वह समझ पाता है कि उसके भीतर कितनी क्षमता है, कितना धैर्य है और कितनी इच्छाशक्ति है। कई बार व्यक्ति को अपनी वास्तविक ताकत का पता ही तब चलता है, जब परिस्थितियां उसे पूरी तरह तोड़ने की कोशिश करती हैं। एक सत्य यह भी है कि प्रत्येक चुनौती केवल बाहरी नहीं होती। अनेक संघर्ष और परिस्थितियों के झंझावात मनुष्य के भीतर भी चलते रहते हैं। भय, असुरक्षा, निराशा, हीनभावना और अकेलापन, ये सब मानसिक चुनौतियां हैं।

बाह्य परिस्थितियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर के संघर्ष अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आंतरिक अंधेरों से लड़ना सीख जाता है, वह जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकता है। इसलिए चुनौतियों की पाठशाला केवल बाहरी संघर्षों की ही नहीं, बल्कि आत्मविजय और आत्ममंथन की भी पाठशाला है।

प्रत्येक चुनौती हमारे व्यक्तित्व की नवीन ढंग से रचना करने के लिए ही हमारे समक्ष उपस्थित होती है। यह पूरी तरह हमारे विवेक और धैर्य पर ही निर्भर करता है कि हम उस चुनौतीस्वरूप अमूल्य अवसर को यों ही जाने देते हैं या उसे पूर्ण समर्पण तथा साहस के साथ स्वीकार करके अपने व्यक्तित्व और अंतर्मन के निखार का माध्यम बनाते हैं। कितना ही प्रचंड झंझावात क्यों न हो, अगर हमने अपने कदम पूरी शक्ति और दृढ़ता के साथ जमा रखे हैं, तो हम विचलित नहीं हो सकते। चुनौतियों के वक्त अगर हमने परिस्थितियों को प्रतिकूल परिवेश के रूप में देखा, तो निस्संदेह हमारी पराजय निश्चित है। चुनौतियों की पाठशाला हमें यह सिखाती है कि प्रतिकूलतम परिस्थिति में भी हम अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का महत्तम दोहन करते हुए रचनात्मकता की ओर कैसे अग्रसर हों।

चुनौतियों की पाठशाला हमें विनम्रता का आभूषण भी प्रदान करती है। सफलता के क्षणों में व्यक्ति कभी-कभी अहंकार का शिकार हो जाता है, लेकिन कठिन परिस्थितियां उसे वास्तविकता का बोध कराती हैं। वे उसे यह समझाती हैं कि जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। प्रत्येक नई चुनौती एक नया पाठ लेकर आती है और हर संघर्ष एक नया अनुभव प्रदान करता है। चुनौतियां जीवन का अनिवार्य अंग हैं। उनसे बचना संभव नहीं है, लेकिन उनसे कुछ न कुछ सीखना अवश्य संभव है। जीवन की हर कठिनाई अपने साथ एक नया अनुभव, एक नई सीख और एक नई संभावना लेकर आती है। जो व्यक्ति चुनौतियों को अपनी पाठशाला बना लेता है, वह परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है।

बाल झड़ने और सफेद होने से छुटकारा दिलाएगा घर पर बना आंवला-मेथी तेल

कम उम्र में बालों के सफेद होने और झड़ने की समस्या का विश्लेषण करते हुए यह लेख घर पर निर्मित आंवला-मेथी तेल के लाभों पर केंद्रित है। इसमें विटामिन सी और एंटी-ऑक्सीडेंट्स की उपस्थिति बालों को जड़ से मजबूती प्रदान करने के साथ प्राकृतिक पोषण सुनिश्चित करती है। आंवला तेल रेसिपी, हेयर फॉल कंट्रोल और नेचुरल हेयर केयर जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह तेल एक प्रभावी आयुर्वेदिक विकल्प है।

कम उम्र में आपके बाल सफेद या जरुरत से ज्यादा झड़ रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए हैं। यदि आप आंवला का तेल बालों में लगाते हैं, तो इससे बाल झडने और सफेद होने की समस्या कम हो जाती है। अब बाजार के केमिकल युक्त वाले तेल को छोड़कर घर पर ही तेल बनाकर बालों में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको आप आसानी से घर पर बना सकती हैं।

बालों के लिए आंवला तेल रेसिपी

खासतौर पर आंवला का तेल बालों के लिए औषधि मानी जाती है, जो लोग नियमित रुप से इस तेल को लगाते हैं, उनके बालों में ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है और सफेद बालों को बढ़ने से रोका जा सकता है। इसमें पाए जाने वाले विटामिन सी और एंटी-ऑक्सीडेंट्स बालों को जड़ों से मजबूत देन में मदद करता है। आइए आपको इस तेल को बनाने की विधि और लगाने का तरीका बताते हैं-

सामग्री

- 10-12 ताजे आंवला
- 1 छोटा चम्मच मेथी दाना
- 1 कप नारियल का तेल

तेल बनाने की विधि

- सबसे पहले एक चम्मच मेथी दाना को रातभर भिगोकर रख दें।
- तेल बनाने के लिए आंवला को अच्छे से धोकर उनके बीज अलग करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
- भीगे हुए मेथीदाना और आंवला के टुकड़ों को मिक्सी जार में डालकर पीस लें।
- आप चाहे तो इनको ऐसे ही तेल में डाल सकते हैं।
- गैस पर कड़ाही रखें और इसमें नारियल का तेल डालें।
- तेल हल्का गरम हो जाए, तो इसमें आंवला और मेथीदाना डालें।
- अब इस तेल के मिश्रण को धीमी आंच पर कम से कम 15 मिनट तक पकने दें। इससे आंवला और मेथी के पोषक तत्व तेल में समाहित हो जाएंगे।
- आंवला हल्के भूरे रंग के दिखने लगे या तेल से आंवले के मिश्रण वाली सुगंध आने लगे तो समझें कि तेल तैयार हो गया है।
- इस मिश्रण को रूम के नॉर्मल टेंपरेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें।
- जब तेल ठंडा हो जाएगा, तो इसे किसी कंटेनर में स्टोर करके रख दें।
- तैयार है घर का बना हुआ आंवला तेल।

तेल लगाने का सही तरीका

आप आंवले के तेल को हफ्ते में दो बार सिर धोने से पहले लगा सकते हैं।

बालों में तेल अप्लाई करने से पहले इसे हल्का गुनगुना कर लें। फिर हाथेली पर लेकर स्कैल्प में हल्के हाथ से मसाज करें। फिर 5-6 मिनट तक मसाज करें और बाद में माइल्ड शैंपू से हेयर्स धो लें।

लद्दाख की वादियों में सुकून और रोमांच

आकांशा गर्ग

रोजमर्रा की भागदौड़ से बचने और कामकाज से मिल रहे तनाव को दूर करने के लिये अगर इस महीने कहीं जाना है, तो लद्दाख का टूर बनाइये। आसमान को सीधे जमीन से मिलाने वाली यह जगह रोमांच, सुकून और आनंद सबकुछ एक साथ देती है। यहां स्वच्छ पानी वाली नीली झीलें, ऊंचे-ऊंचे रहस्यमयी पहाड़ और सुकून भरी ठंडी हवाएं स्वर्ग होने का अहसास कराती हैं। इसीलिये तो हर घुमक्कड़ अपनी बकेट लिस्ट में लद्दाख को एक सपने की तरह सजाकर रखता है।

अगर आप भी यहां की दुनिया को अपनी आंखों से देखने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक आईआरसीटीसी ने जबरदस्त टूर पैकेज दिया हुआ है। इस पैकेज का नाम है 'लेह विद तुरतुक'। इस पैकेज में 6 रात और 7 दिन का है। सफर की शुरुआत ऐतिहासिक शहर हैदराबाद से होगी। टूर पैकेज में फ्लाइट से लेकर होटल में ठहरना, सुबह का नाश्ता और रात का खाना, घूमने के लिये बस या कैब, ट्रैवल इंश्योरेंस और आपातकाल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर आदि सबकुछ मिलेगा। टूर बुक करने वाले पर्यटकों के लिये लद्दाख जाने का परमिट मुहैया कराया जाएगा। आईआरसीटीसी ने लद्दाख टूर का खर्च 37, 070 रुपए तय किया है। टूर प्लान में पहले दिन लेह पहुंचेंगे, फिर पूरे दिन आराम करेंगे, ताकि आपका शरीर वहां की ठंडी हवा और ऊंचाई के अनुकूल हो सके। शाम को लोकल मार्केट घूमने का मौका मिलेगा और दूसरे दिन लेह में घूमने का अवसर दिया जाएगा। यहां विश्वप्रसिद्ध शांति स्तूप, लेह पैलेस और 'हॉल ऑफ फेम' देखने को मिलेगा। तीसरे दिन शाम वैली, गुरुद्वारा पत्थर साहिब और फिर रहस्यमयी 'मैग्नेटिक हिल' की सैर करने को मिलेगी। इस चुम्बकीय पहाड़ी पर आप रहस्यमयी खिंचाव को खुद महसूस करेंगे। वैज्ञानिकों का मत है कि इस पहाड़ी पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण मौजूद है। टूर पैकेज में चौथे दिन खारदुंग ला दर्रा पार करके नुब्रा वैली ले जाया जाएगा, जहां ऊंचे-ऊंचे टीले और ऊंट की सवारी

> टूर प्लान में पहले दिन लेह पहुंचेंगे, फिर पूरे दिन आराम करेंगे, ताकि आपका शरीर वहां की ठंडी हवा और ऊंचाई के अनुकूल हो सके। शाम को लोकल मार्केट घूमने का मौका मिलेगा और दूसरे दिन लेह में घूमने का अवसर दिया जाएगा।

की मौज लीजिए।

पांचवें दिन चीन सीमा से सटे भारत के अंतिम गांव 'तुरतुक' की सैर कराई जाएगी। छठवें दिन विश्वप्रसिद्ध पैंगोंग झील का दीदार करने को मिलेगा। यह बहुत बड़ी और नीले पानी की खूबसूरत झील है। इस पूरे टूर में आपको भारत के अलावा चीन के कुछ हिस्से में भी घूमने को मिलेगा। अंत में सातवें दिन लेह वापस आना और एयरपोर्ट के लिए रवाना होना होगा।

रखनी होंगी ये सावधानियां

लद्दाख काफी ऊंचाई पर है, इसलिए ट्रिप पर जाने से पहले कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। कम ऑक्सीजन और ज्यादा ऊंचाई की वजह से 'एक्यूट माउंटेन सिकनेस' हो सकती है। यात्रा पर निकलने से पहले अपने डॉक्टर से पूछकर कुछ जरूरी दवाएं अवश्य रख लें। शरीर को हाइड्रेटेड रखें। पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज पीते रहें। बहुत ज्यादा खाना खाने, शराब पीने और एंटी-डिप्रेसेंट दवाओं से बचें। नुब्रा और पैंगोंग के टेंट/कैंप्स में बिजली कुछ घंटों के लिए ही आती है। सुबह नहाने के लिए सोलर या बाल्टी से गर्म पानी मिलता है। पैंगोंग में मोबाइल नेटवर्क, वाई-फाई, एटीएम, बैंक या पेट्रोल पंप की सुविधा नहीं है। इसलिए जरूरी कैश साथ लेकर ही जाएं। अगर आप ट्रिपल शेयरिंग रूम लेते हैं तो तीसरे व्यक्ति के लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा गद्दा ही दिया जाएगा।

तुरतुक से पैंगोंग तक रोमांचक सफर, लद्दाख टूर में मिलेंगे यादगार नजारे

जब आप टूर के दौरान तुरतुक गांव पहुंचेंगे तो वहां की अलग जीवनशैली और संस्कृति आपको रोमांचित करेगी। परंपरागत पहनावे में महिलाएं और पुरुष मिलेंगे और उनका खान-पान व रहने के तरीके आपको अच्छा अनुभव कराएंगे। लद्दाख की पैंगोंग झील 120 किलोमीटर लंबी है। खारे पानी की इस अद्भुत झील को देखने दुनिया भर के पर्यटक पहुंचते हैं। भारत और एशियाई देशों में फिल्म '3 इडियट्स' को देखने के बाद यह जगह पर्यटकों की पहली पसंद बन गई है। इस झील का कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ चीन में। पैंगोंग से लेह वापस लौटते समय रास्ते में चांगला पास, थिकसे मोनेस्ट्री और शे पैलेस के नजारे भी देखने को मिलेंगे। टूर पैकेज में आईआरसीटीसी ने पर्यटकों के लिये वे सारी सुविधाएं मुहैया कराई हुई हैं, जो उनके लिये जरूरी हैं और जिनसे तनावमुक्त होकर सैर करने का मौका मिलता है। टूर के दौरान 3 रातें लेह में, 2 रातें नुब्रा में और एक रात पैंगोंग में बिताना होगा। टूर पैकेज में गाइड का खर्च भी शामिल है। ट्रिप में 6 बार सुबह का नाश्ता, 6 बार दोपहर का खाना और 6 बार रात का खाना शामिल है। घूमने के लिये शेयरिंग वाली नॉन-एसी कार मिलेगी। ट्रैवल इंश्योरेंस और स्मारकों के टिकट भी इस पैकेज में होंगे। हर दिन, हर व्यक्ति को एक लीटर पानी की बोतल मिलेगी और आपातकाल के लिये कार में ऑक्सीजन सिलेंडर और टूर मैनेजर साथ रहेगा।

क्या आपको भी ऑफिस पहुंचते ही गुस्सा आने लगता है?

सावधान! मानसिक तनाव बिगाड़ सकता है आपकी सेहत

डॉ. मुकुल शर्मा

आजकल ऑफिस कल्चर में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक समय था जब लोगों को ऑफिस में काम करने से रिलैक्शन मिलता था, लेकिन आज के युवाओं में ऑफिस आते ही उन्हें स्ट्रेस फील होने लगता है। वैसे वर्क की टेंशन में कई बार हल्के लक्षणों को ज्यादातर लोल अनदेखा कर देते हैं।

इन लक्षणों में से बीपी एक आम समस्या मानी जा रही है। जानकार के मुताबिक लंबे समय से लैपटॉप पर काम करना, लगातार मानसिक तनाव, नींद की कमी, देर रात तक जागना और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण से 25 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों में भी हाई बीपी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि, टेंशन की बात यह है कि कई लोगों का बीपी डॉक्टर के क्लिनिक में नॉर्मल रहता है, जबकि ऑफिस या काम के दौरान लगातार बढ़ जाता है। इस परिस्थिति को मास्क्ड हाइपरटेंशन कहा जाता है। कई अध्ययनों में पता चलता है कि लोगों में भविष्य में हार्ट अटैक , स्ट्रोक और किडनी रोग का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा हो सकता है।

मास्क्ड हाइपरटेंशन क्या है?

एनसीबीआई के अनुसार, मास्क्ड हाइपरटेंशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें डॉक्टर के क्लिनिक में ब्लड प्रेशर सामान्य 140/90 से कम नजर आता है, हालांकि घर, ऑफिस, यात्रा या दैनिक गतिविधियों के दौरान यह लगातार हाई रहता है। यह 'वाइट कोट हाइपरटेंशन' का उल्टा रुप होता है।

जैसे कि क्लिनिक में बीपी बढ़ जाता है लेकिन बाहर सामान्य रहता है। एक्सपर्ट के मुताबिक, इस बीमारी का सबसे बड़ा खतरा यही है कि सामान्य जांच में पकड़ में नहीं आता है। इसलिए मरीज को लगता है कि उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, जबकि शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं और हृदय पर दबाव बना रहता है।

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, जो सामान्य हाई ब्लड प्रेशर में व्यक्ति का बीपी हर जगह घर, ऑफिस और क्लिनिक लगातार ऊंचा रहता है। लेकिन मास्कड हाइपरटेंशन सिर्फ रोजमर्रा की परिस्थितियों में बीपी बढ़ता है, जबकि डॉक्टर के पास जाने पर नॉर्मल हो जाता है।

युवाओं में इसके मामले क्यों बढ़ रहे हैं?

सीडीसी के अनुसार, आज की व्यस्त और तनावपूर्ण जीवनशैली मास्क्ड हाइपरटेंशन का एक अहम कारण बन सकता है। लंबे समय तक ऑफिस में बैठे रहना, काम की डेडलाइन का दबाव, मोबाइल और लैपटॉप का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, नींद की कमी, अधिक कैफीन, धूम्रपान और पैकेज्ड या प्रोसेस्ड खाना ब्लड प्रेशर पर असर डालते हैं। इन आदतों से शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन का स्तर बढ़ सकता है। नतीजतन, व्यक्ति की रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ा रह सकता है, लेकिन घर पर आराम करते समय या डॉक्टर के क्लिनिक में जांच कराने पर यह सामान्य दिखाई दे सकता है। इसी वजह से इसे पहचानना कई बार मुश्किल होता है।

बचाव कैसे करें

- सप्ताह में कम से कम 150 मिनट व्यायाम करें।
- ऑफिस के समय हर 45-60 मिनट में उठकर चलें।
- नमक का सेवन सीमित करें।
- धूम्रपान और शराब का सेवन से बचें।
- रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें।
- मेडिटेशन और गहरी सांस लेने जैसी तनाव कम करने वाली तकनीकी अपनाएं।
- अगर आप परिवार में हाई बीपी का इतिहास है, तो नियमित तौर पर घर पर ही बीपी जांच करें।

नाइट आउल्स सावधान! देर रात जागने और खाने से बिगड़ सकता है मेटाबॉलिज्म

आजकल युवाओं में रात-रात भर जागना दिनचर्या का मुख्य हिस्सा बन गया है। माना जाता है देर रात जागना के सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन फिर भी हम सभी इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं। हालिए एक शोध में पता चला है कि देर रात जागने की आदत खतरे की घंटी बजा दी है। क्या आप भी देर रात तक जागने और कुछ न कुछ खाते रहने की आदत है, तो यह खबर आपके लिए काफी जरुरी है।

हालिया शोध विश्लेषण के अनुसार देर रात तक जागने और खाने की आदत मेटाबॉलिज्म को गंभीर रूप से प्रभावित करती है जिससे शरीर में फैट और ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि भोजन की मात्रा से अधिक भोजन का समय स्वास्थ्य परिणामों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेटाबॉलिज्म, हेल्थ रिसर्च और नाइट आउल्स जैसे कारकों का यह प्रभाव आधुनिक जीवनशैली के लिए एक बड़ी चेतावनी है।

क्या कहता है नया शोध?

हाल ही में 'फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन' जर्नल में प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि जो लोग देर रात जागते हैं और उस दौरान अधिक एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली चीजें खाते हैं, उनके शरीर में गंभीर बदलाव देखने को मिलते हैं।

इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है

- शरीर में फैट का कुल प्रतिशत बढ़ना
- पेट की चर्बी में इजाफा
- ब्लड शुगर के स्तर का बढ़ना
- लिपिड लेवल का अधिक होना

समय का है सारा खेल

यह रिसर्च ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ, स्पोर्ट एंड सोशल वर्क की शोधकर्ता रोजेन क्रूगर ने लीड किया है। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी खाने की पसंद, हमारे व्यवहार और मेटाबॉलिज्म पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है।

इस अध्ययन में एक अनोखी बात पता चला है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोग और देर रात तक जागने वाले लोग दोनों ही दिनभर में करीब एक जैसा ही मात्रा में खाना या एनर्जी लेते हैं। दोनों की खुराक में काफी अंतर देखने को मिलता है। असली समस्या तो यह है कि आप किस समय खा रहे हैं। सही समय पर भोजन न करना असली समस्या की जड़ है।

महिलाओं पर की गई खास स्टडी

शोध करने वाले लोग इस नतीजे पर पहुंचे है कि 18 से 45 साल की उम्र की 287 महिलाओं को अपने अध्ययन में शामिल किया था। इस अवधि में महिलाओं के खान-पान की आदतों को बारीकी से देखा गया, जिसमें कई हैरान करने वाले पैटर्न देखा गया है।

सुबह कम आहार खाएं

दरअसल, जो महिलाएं देर रात तक जागती थीं, उनमें सुबह के समय कम एनर्जी और कम प्रोटीन वाला भोजन लेने की संभावना काफी ज्यादा देखी गई है।

रात में अनहेल्दी खान-पान

सुबह कम खाने की भरपाई को पूरा करने के लिए महिलाएं रात के समय खूब फूड्स का सेवन करती थीं। देर रात में अधिक एनर्जी, अधिक कार्बोहाईड्रेट और फैट से भरपूर चीजें खाती है।

पोषक तत्वों की कमी

जो महिलाएं शाम और रात के समय ज्यादा एक्टिव रहती हैं, उन्हें उन महिलाओं (जो कि सुबह या दिन के बीच एक्टिव रहती हैं) की तुलना में कम माइक्रोन्यूट्रिएंट और कम एनर्जी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया।

आज महानायक लेकिन कभी सेट पर मिली थी फटकार

शुरूआत में बहुत डांट पड़ती थी: अमिताभ बच्चन

दक्ष कोटियन

अमिताभ बच्चन आज हिंदी सिनेमा के महानायकों में शुमार हैं। उनकी आवाज अभिनय और व्यक्तित्व की अपनी अलग पहचान है। दशकों से वह फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और आज भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। लेकिन जिस मुकाम पर अमिताभ बच्चन आज खड़े हैं वहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था। करियर के शुरूआती दौर में उन्हें भी कई बार आलोचना और कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा था। कौन बनेगा करोड़पति 18 के एक स्पेशल एपिसोड में बिग बी ने अपने संघर्ष के दिनों से जुड़ा ऐसा ही किस्सा सुनाया जिसने उनके प्रशंसकों का ध्यान खींचा।

केबीसी 18 के इस खास एपिसोड में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के गोल्ड मेडलिस्ट लवलीना बोगोहैंन के साथ झंडू कुमार शर्मिला धंकर और अस्मिता डे भी पहुंचीं। बातचीत के दौरान अस्मिता डे ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि क्या उन्हें कभी फिल्म के सेट पर डांट सुननी पड़ी है। सवाल सुनते ही बिग बी ने अपने पुराने दिनों को याद किया और बताया कि शुरूआत में उन्हें काफी डांट पड़ती थी। अमिताभ ने बताया कि उन्हें यहां तक सुनना पड़ा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता तुम बहुत लंबे हो घर जाओ।

अमिताभ बच्चन के इस खुलासे से साफ है कि उनके शुरूआती करियर में उनकी लंबाई को लेकर भी सवाल उठाए जाते थे। जिस कद को आज उनकी पहचान का हिस्सा माना जाता है उसी को कभी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि लंबे कद वाला यह कलाकार आगे चलकर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बनेगा। अमिताभ ने जिस सहज अंदाज में यह किस्सा साझा किया उससे उनके संघर्ष के दिनों की तस्वीर सामने आती है। अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर कई उतार चढ़ाव से भरा रहा है। शुरूआती दौर में उन्हें सफलता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। कई फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन उन्होंने आलोचनाओं और असफलताओं को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। धीरे धीरे उनकी अभिनय क्षमता और अलग अंदाज ने दर्शकों के बीच जगह बनाई और देखते ही देखते वह बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए।

केबीसी में अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी निजी जिंदगी से जुड़े मजेदार किस्से भी बताते हैं। एक अन्य एपिसोड में उनसे पूछा गया कि अगर वह शूटिंग की वजह से देर रात घर पहुंचते हैं तो क्या पत्नी जया बच्चन से उन्हें डांट सुननी पड़ती है। इस पर बिग बी ने मजाकिया अंदाज में बताया कि वह पहले से ही परिवार को सूचना दे देते हैं। अमिताभ के मुताबिक अगर उन्हें पता होता है कि शूटिंग की वजह से देर होगी तो वह सुबह परिवार के ग्रुप में संदेश भेजकर बता देते हैं कि आज देर से घर आएंगे और खाने पर उनका इंतजार न किया जाए। उन्होंने बताया कि इस तरह पहले से सूचना देने पर डांट से बच जाते हैं लेकिन अगर बिना बताए देर हो जाए तो फिर डांट पड़ना तय है। अमिताभ का यह अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आता है क्योंकि इससे महानायक की जिंदगी का एक घरेलू और सामान्य पहलू भी सामने आता है। वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन पिछली बार रजनीकांत के साथ फिल्म वेट्टैयन में नजर आए थे। दोनों ने लंबे समय बाद एक साथ स्क्रीन शेयर की थी। बॉलीवुड में उनकी पिछली प्रमुख फिल्म ऊंचाई थी जो 2022 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा वह कई फिल्मों में वॉइस ओवर और स्पेशल अपीयरेंस भी दे चुके हैं। अब अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों को उनकी अगली बड़ी फिल्म कल्कि 2898 एडी 2 का इंतजार है। फिल्म में उनके साथ प्रभास और कमल हासन जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे। बिग बी का सफर यह बताता है कि आज जिस कलाकार को दुनिया महानायक के नाम से जानती है उसे भी कभी अपने कद अभिनय और क्षमता को लेकर आलोचना सुननी पड़ी थी। लेकिन उन्होंने उन बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और लगातार मेहनत करते हुए ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा।

कभी पिता के पुराने स्कूटर पर दुकान का सामान लाते थे 'यश' आज हैं सुपरस्टार

यश की पहचान धीरे धीरे कन्नड़ सिनेमा से निकलकर पूरे देश में बनी। केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 की सफलता ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया। इसके बाद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। अब उनकी अगली बड़ी फिल्म टॉक्सिक को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है।

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार यश आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। केजीएफ फ्रेंचाइजी में रॉकी भाई के किरदार ने उन्हें देशभर में जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई और अब अभिनेता अपनी अगली बड़ी फिल्म टॉक्सिक को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। हाल ही में आप की अदालत में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए यश ने बताया कि फिल्मी दुनिया में पहचान बनाने से पहले उन्होंने परिवार की मदद के लिए किराने की दुकान तक संभाली थी। उन्होंने कॉलेज के दिनों से जुड़ी ऐसी यादें भी साझा कीं जब पिता के पुराने स्कूटर को लेकर उन्हें हीन भावना महसूस होती थी।

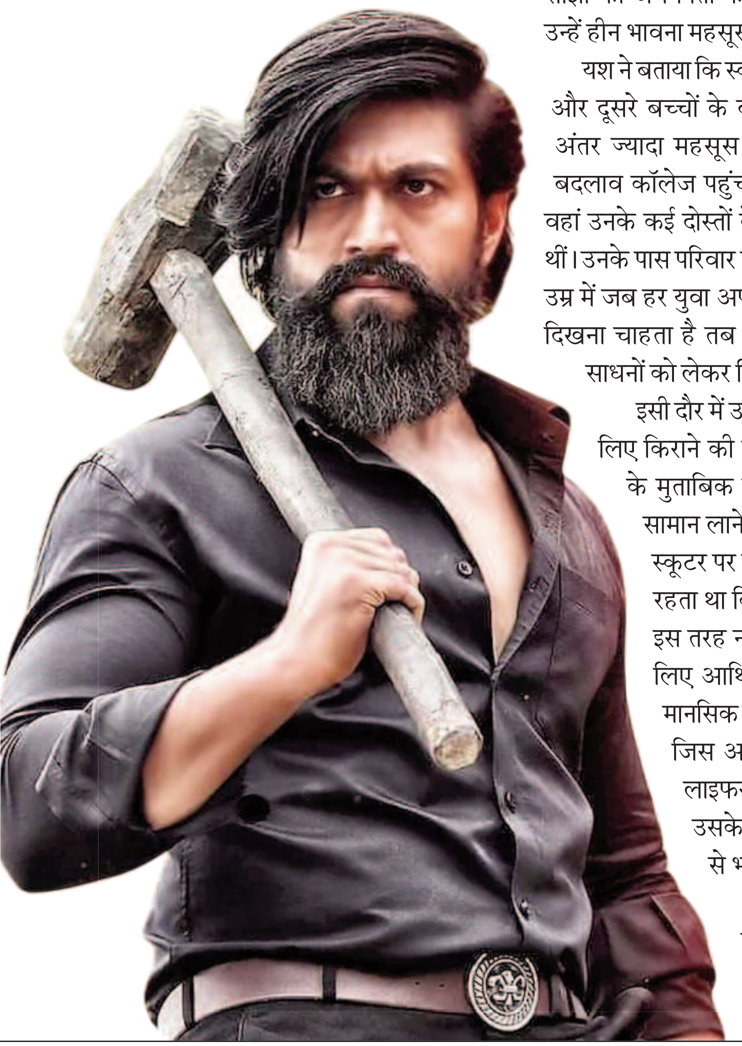

यश ने बताया कि स्कूल के दिनों में उन्हें अपने और दूसरे बच्चों के बीच आर्थिक स्थिति का अंतर ज्यादा महसूस नहीं होता था। असली बदलाव कॉलेज पहुंचने के बाद नजर आया। वहां उनके कई दोस्तों के पास बाइक और कारें थीं। उनके पास परिवार का पुराना स्कूटर था। उस उम्र में जब हर युवा अपने दोस्तों के बीच बेहतर दिखना चाहता है तब यश को अपने साधारण साधनों को लेकर झिझक होने लगी थी।

इसी दौर में उन्होंने परिवार की मदद के लिए किराने की दुकान भी शुरू की। यश के मुताबिक कई बार दुकान के लिए सामान लाने के लिए उन्हें उसी पुराने स्कूटर पर जाना पड़ता था। उन्हें डर रहता था कि कहीं उनके दोस्त उन्हें इस तरह न देख लें। वह दौर उनके लिए आर्थिक संघर्ष के साथ साथ मानसिक दबाव वाला भी था। आज जिस अभिनेता की फिल्मों और लाइफस्टाइल की चर्चा होती है उसके पीछे संघर्ष और असुरक्षा से भरा वह दौर भी रहा है।

यश ने अपने माता पिता के योगदान को भी बेहद अहम बताया। उनके मुताबिक परिवार भले ही उनके लिए बड़ी संपत्ति नहीं बना पाया लेकिन माता पिता ने उन्हें जिंदगी के जरूरी सबक दिए और हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया। यही भरोसा आगे चलकर उनके आत्मविश्वास की ताकत बना। यश की कहानी इस बात की मिसाल है कि किसी व्यक्ति की शुरूआती आर्थिक स्थिति उसकी मंजिल तय नहीं करती। लगातार मेहनत और सही मौके के साथ परिस्थितियां बदली जा सकती हैं।

यश की पहचान धीरे धीरे कन्नड़ सिनेमा से निकलकर पूरे देश में बनी। केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 की सफलता ने उन्हें पैन इंडिया स्टार बना दिया। इसके बाद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। अब उनकी अगली बड़ी फिल्म टॉक्सिक को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। फिल्म में यश के साथ नयनतारा कियारा आडवाणी हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है और यह 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

टॉक्सिक की रिलीज से पहले यश लगातार प्रमोशन में व्यस्त हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और इसे बड़े स्तर पर रिलीज करने की तैयारी है। ऐसे समय में अभिनेता का अपने संघर्ष के दिनों को याद करना उनके प्रशंसकों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह दिखाता है कि आज का रॉकी भाई कभी बेहद सामान्य परिस्थितियों से निकलकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। यश की कहानी बताती है कि सफलता के चमकदार मुकाम के पीछे अक्सर ऐसे दौर छिपे होते हैं जिनमें व्यक्ति को खुद पर भरोसा बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है।

2027 विश्वकप में रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा बरकरार, दोनों की दावेदारी मजबूत

अजीत शर्मा

रोहित शर्मा और विराट कोहली को रोकना अब किसी के लिये संभव नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के इन दोनों धुरंधरों का दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले एकदिनी विश्वकप 2027 में खेलना तय है। हालांकि टीम का ऐलान टूर्नामेंट से एक महीने पहले होगा, लेकिन इन अटकलों को विराम लग गया है कि मुख्य कोच गौतम गंभीर की रोहित शर्मा और विराट कोहली को रोकने की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी।

पिछले दिनों इंग्लैंड से हुई एकदिवसीय सीरीज में इन दोनों दिग्गजों ने जिस तरह अपना दमखम दिखाया, यह साबित हो गया कि बड़ी उम्र के बावजूद दोनों में क्रिकेट कायम है और भारत को विश्वकप जिताने में ये बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में 66 गेंदों पर 65 और तीसरे में 60 बॉल पर 74 रन ठोंककर अपनी जबरदस्त फॉर्म का परिचय दिया। रोहित शर्मा ने तो तीसरे मैच में 138 रन बनाकर अपना जलवा कायम रहने का सबूत दे दिया। दोनों के इस शानदार प्रदर्शन के बाद भी अगर कोई यह अटकल लगाता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को विश्वकप टूर्नामेंट के लिये टीम से हटाया जा सकता है तो यह मूर्खता होगी।

दरअसल, रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर के बीच के रिश्ते जगजाहिर हैं। इनके फैंस और मीडिया में इस सवाल पर अक्सर चर्चा होती रहती है। सच्चाई जो भी हो, टीम का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि खिलाड़ी कैसा खेल रहे हैं और उनमें कितना दमखम है? हालांकि पिछले दिनों गौतम गंभीर ने मीडिया के सामने साफ किया कि वे किसी के विरोधी नहीं हैं और टीम के सभी वरिष्ठ खिलाड़ी देश के लिए अपना बेस्ट देने के लिए एक ही पेज पर हैं। टीम प्रबंधन ने भी इन दिग्गजों के बीच किसी भी विवाद से इनकार करते हुए इसे अफवाह कहा है।

अगला विश्व कप अक्टूबर-नवंबर 2027 में होना है, तब तक रोहित की उम्र 40 और कोहली की 39 वर्ष हो जाएगी। विश्व क्रिकेट में इन दोनों से ज्यादा उम्रदराज खिलाड़ी खेलते देखे जाते रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन और जहीर अब्बास जैसे दिग्गजों का मानना है कि चूंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली फिट हैं और रन बना रहे हैं, लिहाजा उम्र कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल दोनों दिग्गजों को चोट से बचे रहना होगा। उनका अनुभव और फॉर्म भारतीय टीम के लिये बहुत उपयोगी रहेगी। फिलहाल, विश्वकप 2027 के लिये रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा जिन खिलाड़ियों को टीम के संभावित खिलाड़ी कहा जा रहा है, उनमें शुभमन गिल, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत जैसे नाम प्रमुख हैं। ऋषभ की दावेदारी उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगी। इनके अलावा यशस्वी जायसवाल, रविन्द्र जडेजा, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रिंस यादव के नाम की चर्चा हो रही है। यह तय है कि शुभमन गिल ही भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे।

वनडे क्रिकेट के 5000 मैच पूरे, सचिन तेंदुलकर का 18426 रन का रिकॉर्ड आज भी कायम

वनडे क्रिकेट 7 अगस्त को एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। स्कॉटलैंड और कनाडा के बीच खेला गया मुकाबला इस फॉर्मेट के इतिहास का 5000वां वनडे मैच बना। स्कॉटलैंड ने इस यादगार मुकाबले में कनाडा को 9 रन से हराकर इस ऐतिहासिक मैच को अपने नाम किया। टेस्ट क्रिकेट के बाद शुरू हुआ वनडे फॉर्मेट कई दशकों तक क्रिकेट प्रशंसकों के मनोरंजन का प्रमुख जरिया रहा है। हालांकि अब टी20 क्रिकेट की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ते मुकाबलों के कारण वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

क्रिकेट के तीनों प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट पर नजर डालें तो वनडे में अब तक सबसे ज्यादा मुकाबले खेले गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 2628 मैच पूरे हो चुके हैं, जबकि टी20 क्रिकेट में भी 4059 मुकाबले खेले जा चुके हैं। टी20 के लगातार बढ़ते विस्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में यह फॉर्मेट वनडे के कुल मुकाबलों की संख्या को पीछे छोड़ सकता है। इसके बावजूद वनडे क्रिकेट का इतिहास कई ऐसे रिकॉर्ड्स से भरा हुआ है, जिन्हें तोड़ना आज भी बड़ी चुनौती माना जाता है।

वनडे क्रिकेट के 5000वें मुकाबले के मौके पर इस फॉर्मेट के लंबे समय तक कायम रहने वाले रिकॉर्ड्स की चर्चा भी हुई। इनमें सबसे प्रमुख रिकॉर्ड भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। सचिन ने अपने वनडे करियर में 18426 रन बनाए और वह आज भी इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मुकाबला 2012 में खेला था, लेकिन उनके संन्यास के वर्षों बाद भी कोई बल्लेबाज उनके इस आंकड़े को पार नहीं कर सका है।

सचिन के सबसे करीब विराट कोहली हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 14941 रन बनाए हैं। हालांकि सचिन और कोहली के बीच अब भी 3485 रनों का अंतर है। कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और उनका पूरा ध्यान वनडे क्रिकेट पर है, लेकिन उनकी उम्र और वनडे मुकाबलों की घटती संख्या को देखते हुए सचिन के रिकॉर्ड तक पहुंचना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। यही वजह है कि 18426 रन का आंकड़ा वनडे क्रिकेट के सबसे मुश्किल और लंबे समय तक कायम रहने वाले रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया है।

वनडे इतिहास में सिर्फ सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड ही लंबे समय तक कायम नहीं रहा है। श्रीलंका के नाम सबसे ज्यादा टीम टोटल का रिकॉर्ड लंबे समय तक रहा। विव रिचर्ड्स का व्यक्तिगत सर्वोच्च स्कोर, चमिंडा वास के शानदार गेंदबाजी आंकड़े और मुथैया मुरलीधरन के सबसे ज्यादा विकेट जैसे रिकॉर्ड्स ने भी वर्षों तक क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा। शाहिद अफरीदी के सबसे तेज शतक और सनथ जयसूर्या के सबसे तेज अर्धशतक के रिकॉर्ड भी लंबे समय तक चर्चा में रहे। सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड भी लंबे समय तक कायम रहा है। इसके अलावा वकार यूनिस ने सबसे ज्यादा पांच विकेट हॉल के रिकॉर्ड पर भी वर्षों तक अपना दबदबा बनाए रखा। वनडे क्रिकेट के 5000 मैच पूरे होने के साथ एक ओर जहां इस फॉर्मेट की गौरवशाली यात्रा का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं सचिन तेंदुलकर का 18426 रन का रिकॉर्ड यह याद दिलाता है कि महान खिलाड़ियों के बनाए कुछ आंकड़े समय के साथ और भी खास हो जाते हैं।

शोर की सीमा टूटी तो जिंदगी भी थमी

बरेली की घटना ने खड़े किए बड़े सवाल

महमूद रजा
बिजनौर

देश में वायु प्रदूषण की तरह तेज आवाज का शोर भी गंभीर समस्या बन गया है। महानगरों से लेकर छोटे कस्बे तक ध्वनि प्रदूषण की जद में हैं। इससे मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकते हैं। लगातार अत्यधिक शोर के संपर्क में रहने से उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, मानसिक तनाव, बहरापन और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कई दफा इसके तात्कालिक एवं गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं।

ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के बरेली में बीते सोमवार को सामने आई, जब सड़क पर तेज आवाज में बज रहे डीजे के पास से गुजरते वक्त साठ वर्षीय महिला की तबीयत बिगड़ जाने से मौत हो गई। सवाल है कि जब ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कानून में सख्त प्रावधान हैं, तो फिर सार्वजनिक स्थलों पर बहुत तेज आवाज में डीजे बजाने या लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति क्यों और कैसे दी जाती है? अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की जाती?

गौरतलब है कि देश में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम के तहत विभिन्न स्थलों पर ध्वनि के स्तर की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर इसके संकेतक लगाने के भी प्रावधान हैं। कई जगह सड़कों के आसपास के रिहाइशी इलाकों को आधिकारिक तौर पर वाहनों के लिए ध्वनि निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी के लिए विशेष यंत्र लगाए गए हैं। मगर इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद तेज आवाज के शोर पर लगाम नहीं लग पा रही है।

जाहिर है कि इसके लिए संबंधित महकमों की लापरवाही ही जिम्मेदार है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को तो बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन ऐसी ही गंभीरता सड़कों पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने में नजर नहीं आती है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि सड़क पर तेज आवाज में डीजे बजाने से अगर किसी की जान चली जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? शासन-प्रशासन को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए कि सिर्फ कागजों में कानून बना देने से कुछ नहीं होता, व्यवस्था में सुधार तभी हो पाता है, जब उसे सख्ती से लागू किया जाए।

TCL
GRAND
INDEPENDENCE DAY
UPGRADE
7th - 16th AUGUST 2026
FREE 1 - YEAR EXTENDED WARRANTY*
SAVE UP TO ₹24,990*
10% CASHBACK
UP TO
₹15,000*
C7L SQD-Mini LED TV
Available Sizes: 138cm (55 inch), 163cm (65 inch), 189cm (75 inch), 215cm (85 inch), 248cm (98 inch)
100% BT. 2020 All Scenes Wide Color Gamut
Up to 2176 Precise Dimming Zones
HVA 2.0 Pro Panel
Up to HDR 3000nits
C8L SQD-Mini LED TV
Available Sizes: 138cm (55 inch), 163cm (65 inch), 189cm (75 inch), 215cm (85 inch), 248cm (98 inch)
Ultra Slim Design
WHVA 2.0 Ultra Panel
100% BT.2020 All Scenes Wide Color Gamut
Precise Dimming Series Up to 4032 zones
A400 Pro NXTVISION TV
Available Sizes: 138cm (55 inch), 163cm (65 inch), 189cm (75 inch)
Frame Design
Art Gallery
QD-MiniLED
Matte Screen
P8L Premium QD-Mini LED TV
Available Sizes: 138cm (55 inch), 163cm (65 inch), 189cm (75 inch), 215cm (85 inch), 248cm (98 inch)
Precise Dimming Series
144Hz Native Refresh Rate
High HDR Brightness
ONKYO 2.1 Hi-Fi System
T&C Apply*
ICICI Bank | SBI card | HDFC BANK | AXIS BANK | IDFC FIRST Bank | BOBCARD | scapia | Federal Bank | HSBC | YES BANK | AU SMALL FINANCE BANK
Agra Zone: Agra, Mathura, Firozabad, Mainpuri. (Anil Devnani - 9152809075)
Bareilly Zone: Bareilly, Budaun, Pilibhit, Shahjahanpur. (Deepak Singh - 8923365454)
Meerut Zone: Meerut, Baghpat, Bulandshahr, Gautam Buddha Nagar (Noida), Ghaziabad, Hapur. (Anuj Gupta - 9548285247)
Kanpur Zone: Kanpur, Etawah, Farrukhabad, Kannauj, Auraiya, Kanpur Dehat. (Ehatshamuddin - 8318071391)
Lucknow Zone: Lucknow, Hardoi, Lakhimpur Kheri, Raebareli, Sitapur, Unnao. (Prem Pandey - 8009212363)
Prayagraj Zone: Prayagraj, Fatehpur, Kaushambi, Pratapgarh. (Prasoon Chaurasia - 9369417110)
Varanasi Zone: Varanasi, Chandauli, Ghazipur, Jaunpur (Manoj Kumar Yadav - 9721450046)
Gorakhpur Zone: Gorakhpur, Kushinagar, Maharajganj, Deoria. (Akashmani Tripathi - 9936888366)

राहत टैक्स से फ्रीडम इंटरेस्ट से

नागरिकों के लिए सुनहरा मौका

अवधि
15 अगस्त से 15 दिसंबर, 2026 तक

नगर निकायों में लंबित संपत्ति कर (गृहकर/जलकर/सीवर-कर) हेतु

एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.)

- पूरा बकाया भुगतान करने पर ब्याज एवं सरचार्ज में मिलेगी **100% छूट**
- **ऑनलाइन तथा ऑफलाइन** दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा
- बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए अधिकतम **3 किस्तों** की सुविधा
- बकाया राशि का **1/3 हिस्सा** 30 दिनों में और शेष **2/3 हिस्सा दो मासिक किस्तों** में जमा करने की सुविधा
- 1 अप्रैल, 2026 तक लंबित सभी प्रकार की संपत्तियों के कर पर मिलेगा **OTS का लाभ**

अपने नगर निकाय के कार्यालय आएं,
समय रहते OTS का लाभ उठाएं,
कर के बोझ से मुक्ति पाएं.

OTS अपनाएं ब्याज में पूरी राहत पाएं

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

टोल फ्री नं. : 1533

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

nagarvikas_up UPNagarVikasVibhag NagarVikas_UP @NagarVikasVibhagUP